नई दिल्ली
मंगलवार
29 सितंबर 2026
वर्ष: 13, अंक: 26
पृष्ठ: 08, मूल्य 2 रु0
E-mail
story@sadbhawna.today
sadbhavnatoday@gmail.com
web: www.sadbhawna.today

हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

सद्भावना टुडे

आवाज़ अधिकार की

DELHIN/2014/58158

बिहार में धान खरीद का लक्ष्य 35 लाख से बढ़ाकर...पेज-05

सचिन तेंदुलकर ने ओपनएआई के साथ की..पेज-06

एक नजर

बुलेट ट्रेन के लिए महाराष्ट्र में पहला स्टील पुल तैयार, 1,405 टन है वजन

नई दिल्ली। मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत महाराष्ट्र में पहला स्टील पुल तैयार कर लिया गया है। 100 मीटर लंबा और 1,405 टन वजनी यह पुल ठाणे जिले के भिवंडी में डाइव-अंजुर गांव के पास नासिक हाईवे (राष्ट्रीय राजमार्ग-3) पर बनाया गया है। इस पुल को करीब 1,300 किलोमीटर दूर तमिलनाडु के त्रिची में तैयार किया गया। इसके बाद इसे बड़े ट्रेलरों से महाराष्ट्र लाया गया और यहां जोड़कर निर्धारित स्थान पर स्थापित किया गया। अधिकारियों के अनुसार, यह काम देश में बड़े और जटिल इस्पात ढांचे तैयार करने की बढ़ती क्षमता को दिखाता है। पुल बनाने के दौरान स्टील की कटाई, ड्रिलिंग, वेल्डिंग और पेंटिंग का काम तय मानकों के अनुसार किया गया। इस्तेमाल किए गए स्टील के प्रत्येक बैच की अल्ट्रासोनिक जांच की गई। वेल्डिंग और निगरानी के काम में लगे कर्मचारियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित किया गया था।

निर्माण स्थल पर पुल को जमीन से करीब 17.5 मीटर ऊपर अस्थायी ढांचे पर जोड़ा गया। इसके लिए 22 स्किड व्यवस्था और 54,076 विशेष उच्च क्षमता वाले बोल्ट लगाए गए। पुल की सुरक्षा और लंबे समय तक मजबूती बनाए रखने के लिए विशेष पेंट और कंपन कम करने वाली बेयरिंग भी लगाई गई हैं। पुल को इसके अंतिम स्थान तक पहुंचाने के लिए स्वचालित प्रणाली का इस्तेमाल किया गया। इसमें 150-150 टन क्षमता वाले दो जैक और विशेष मजबूत छड़ों का इस्तेमाल किया गया। राजमार्ग पर यातायात को कम से कम प्रभावित करने के लिए पुल को रात में यातायात रोककर स्थापित किया गया। मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन गलियारे में कुल 28 स्टील पुल बनाए जाने हैं। इनमें से 16 पुलों का काम पूरा हो चुका है। ये पुल राजमार्ग, एक्सप्रेसवे, नदियों और रेलवे लाइनों को पार करने के लिए बनाए जा रहे हैं, जहां लंबे हिस्से को एक ही पुल से पार करना जरूरी होता है।

यूएई निवेशकों के लिए भारत में कई क्षेत्रों में अवसर: गोयल

नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत गति से आगे बढ़ रही है और यूएई के निवेशकों के लिए कई क्षेत्रों में निवेश के व्यापक अवसर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) भारत-यूएई व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण ढांचा है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने मुंबई में भारत और यूएई निवेश पर आयोजित उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल (एचएलजेटीएफआई) की 14वीं बैठक के दौरान अपने संबोधन में यह बात कही। इस बैठक में द्विपक्षीय निवेश प्रवाह बढ़ाने तथा सहयोग के उभरते क्षेत्रों की संभावनाओं का पता लगाने सहित व्यापार और निवेश से जुड़े हुए प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक की सह-अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अबू धाबी निवेश प्राधिकरण (एडीआईए) के प्रबंध निदेशक (एमडी) शेख हामिद बिन जायद अल नाहयान ने की। निवेश पर उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की स्थापना वर्ष 2013 में भारत और यूएई के बीच व्यापार, निवेश तथा आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। पीयूष गोयल ने 'एक्स' पोस्ट पर जारी एक पोस्ट में लिखा यूएई के विदेश व्यापार मंत्री, डॉ. थानी बिन अहमद अल जायोदी से मिलकर खुशी हुई।

गृह मंत्री का आतंकवाद के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' नीति और अगले 10 साल के लिए मजबूत 'प्रहार' तंत्र बनाने पर जोर

अमित शाह ने 'प्रहार- सीटी (आतंकवाद-रोधी) नीति और रणनीति' पर आयोजित सम्मेलन का उद्घाटन किया

नई दिल्ली,एजेंसी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी तरह के आतंकवाद के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाने और आतंकवादी घटनाओं के लगातार विश्लेषण के आधार पर अगले 10 वर्षों के लिए मजबूत तथा ठोस 'प्रहार' तंत्र तैयार करने और उसे थाना स्तर तक पहुंचाने पर जोर दिया है। शाह ने सोमवार को यहां 'प्रहार- सीटी (आतंकवाद-रोधी) नीति और रणनीति' पर आयोजित सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने आतंकवाद से निपटने के लिए 'प्रहार' के हर स्तर पर स्वचालित प्रतिक्रिया प्रणाली को संस्थागत बनाने और सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने की जरूरत बताई, ताकि कार्रवाई में किसी तरह की देरी न हो। सम्मेलन में 'प्रहार' के सात स्तंभों रोकथाम, प्रतिक्रिया, आंतरिक क्षमताओं को एकजुट करना, मानवाधिकार, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली स्थितियों को कम करना, अंतरराष्ट्रीय प्रयासों में तालमेल और समूचे समाज के साथ सामंजस्य पर चर्चा हुई।

गृह मंत्री ने कहा कि 'प्रहार' के प्रत्येक स्तंभ के प्रति परिणाम आधारित दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। उन्होंने इन पहलों के हर बिंदु पर सक्रियता के साथ काम करने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सरकार वर्ष 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को वापस लाई है। उन्होंने कहा कि एजेंसियों के बेहतर समन्वय से सीमापार हथियारों, विस्फोटकों और मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल शहजाद भट्टी नेटवर्क के 40 से अधिक मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया। इस मामले में 15 राज्यों में 100 से अधिक प्राथमिकी दर्ज कर 350 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सरकार ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी घोषित किया है। इस अवसर पर गृह मंत्री ने नया 'प्रत्यर्पण पोर्टल' भी शुरू किया। इससे विदेशों में बैठे भगोड़ों को वापस लाने के प्रयासों में समन्वय बेहतर करने और प्रक्रिया में तेजी लाने में मदद मिलेगी। उन्होंने राज्य पुलिस बलों से विदेशों में बैठे इन भगोड़ों को वापस लाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने वाली विशेष टीम बनाने को कहा। सम्मेलन में केंद्रीय गृह सचिव, विदेश सचिव, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख, 15 राज्यों के पुलिस महानिदेशक और सभी राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के आतंकवाद-रोधी दस्तों के प्रमुख शामिल हुए। अन्य राज्यों के पुलिस महानिदेशक और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लिया।

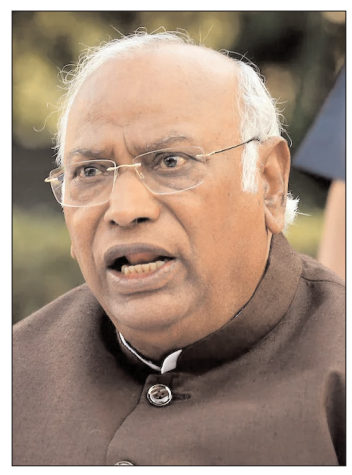

मल्लिकार्जुन खरगे ने बुलाई सीडब्ल्यूसी की बैठक, ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग

नई दिल्ली,एजेंसी। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर जारी विवाद के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार को कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक बुलाई है। बैठक में चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के साथ पार्टी की आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा।

मल्लिकार्जुन खरगे ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर गंभीरता से संघर्ष करेगी और बैठक में सीडब्ल्यूसी के सभी सदस्य अपने सुझाव देंगे। यह मामला केवल किसी एक राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि देश के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को गंभीरता से उठा रही है और सीडब्ल्यूसी की बैठक में आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि आयोग के कामकाज को लेकर उसके अपने लोगों की ओर से भी सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने केरल के पूर्व मुख्य सचिव जीजी थॉमसन के उस दावे का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि 2016 में तत्कालीन आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार ने उन्हें 2019 का लोकसभा चुनाव भाजपा के टिकट पर लड़ने का सुझाव दिया था। थॉमसन के अनुसार, उन्होंने इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया था। खरगे ने इस दावे के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की निष्पक्षता पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यदि किसी अधिकारी ने सेवा में रहते हुए किसी राजनीतिक दल के टिकट पर चुनाव लड़ने का सुझाव दिया था, तो यह चुनाव आयोग की निष्पक्षता से जुड़ा गंभीर प्रश्न है। हालांकि, थॉमसन का यह दावा उनके स्वयं के बयान पर आधारित है और ज्ञानेश कुमार की ओर से इस आरोप पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया की पुष्टि नहीं हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी की। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार को अपने पद से हट जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने मांग की कि इस्तीफा देने के बाद भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। दरअसल, यह विवाद विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर विपक्ष के सवालों के बीच तेज हुआ है। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और संस्थागत जवाबदेही से जुड़े सवालों पर गंभीर चर्चा आवश्यक है। वहीं, चुनाव आयोग की ओर से अपने निर्णयों और एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर स्पष्टीकरण दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में सिलेंडर फटने से दो मंजिला मकान ढहा, 4 लोगों की मौत

फतेहपुर। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में सोमवार की शाम को खाना बनाते समय सिलेंडर में अचानक आग लगने से तेज विस्फोट हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि दो मंजिला मकान भर-भराकर ढह गया। इस घटना में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग घायल हो गये, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया।

मलवां थाना क्षेत्र स्थित कस्बा मलवां निवासी कस्बा निवासी सूरज गुप्ता के घर में खाना बनाते समय सिलेंडर में आग लग गई, जिससे सिलेंडर फटने से मकान भरभरा कर ढह गया। मौके पर परिवार के लोग मौजूद थे। मकान ढहने से कितने लोग मलबे में दबे हैं, इसकी जानकारी की अभी तक नहीं हो पा रही है। ग्रामीणों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और मलबे में दबे लोगों को निकालने का प्रयास शुरू किया जा रहा है। अभी तक 07 लोगों को निकाला जा चुका है, जिनमें 04 लोगों की मौत हो गई। 03 लोग घायल हैं, जिन्हें अल्लीपुर मेडिकल कालेज भेजा गया। प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि सिलेंडर फटने की घटना की सूचना पर पीआरवी व मलवां थाने का फोर्स मौके पर पहुंच कर राहत व बचाव कार्य तेजी से शुरू किया है। इस घटना में अभी तक से 04 लोगों की मौत हो गई और 03 लोग घायल हैं। मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जा चुका है। अभी मलबे को हटाने का कार्य किया जा रहा है, जिससे घटना में हताहतों की पुष्टि हो सके। वही, मृतकों की पहचान भी कराया जा रहा हैं।

उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत तमाम नेताओं ने भगत सिंह की जयंती पर दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने सोमवार को शहीद भगत सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा, 'शहीद भगत सिंह को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। इस निडर क्रांतिकारी ने अटूट साहस और दृढ़ संकल्प के साथ भारत की आज़ादी के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी अदम्य भावना और देशभक्ति पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। मैं उनकी अमिट विरासत को नमन करता हूं और भारत के इस अमर सपूत को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगत सिंह ने अपने अदम्य साहस और वीरता से स्वतंत्रता आंदोलन में नई ऊर्जा का संचार किया। देश के सम्मान के लिए सब कुछ न्योछावर कर देने की उनकी भावना भारत के युवाओं के साहस और संकल्प का प्रतीक है।

सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल नाम और चुनाव चिह्न पर फैसला करने के लिए चुनाव आयोग को दिया चार माह का समय

नई दिल्ली,एजेंसी। उच्चतम न्यायालय ने चुनाव आयोग को अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस नाम और चुनाव चिह्न पर दावे से जुड़े विवाद का निपटारा चार महीने के भीतर करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने दोनों पक्षों को आयोग के समक्ष चार सप्ताह के भीतर अपने हलफ़नामे और जवाबी हलफ़नामे दाखिल करने का निर्देश दिया और स्पष्ट किया कि इस मामले में दलीलें तय समय के भीतर पूरी हो जानी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और वी. मोहना की पीठ ने सुश्री ममता बनर्जी की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिये, जिसमें उन्होंने गुटीय विवाद के बीच तृणमूल नाम और उसके 'फूल और घास' वाले चुनाव चिह्न को फ्रीज़ करने के चुनाव आयोग के अंतरिम फ़ैसले को चुनौती दी थी।

न्यायालय का यह निर्देश चुनाव आयोग की उस दलील के बाद आया जिसमें कहा गया था कि बड़ी संख्या में हलफ़नामों वाले चुनाव चिह्न विवादों में समय लगता है। पीठ ने प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया । चुनाव आयोग ने पार्टी के मूल नाम और चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर सुश्री बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को अंतरिम तौर पर ममता अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस नाम तथा 'फुटबॉल खिलाड़ी' चुनाव चिन्ह आवंटित किया है। अरूप रॉय गुट को डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस नाम तथा 'लिफाफा' चुनाव चिह्न दिया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और कल्याण बंद्योपाध्याय ने पीठ को अवगत कराया कि ममता बनर्जी गुट ने जुलाई में ही अपना जवाब दाखिल कर दिया था, जबकि विरोधी गुट को अभी अपना जवाब दाखिल करना है।

यूपीआई लेनदेन पर शुल्क लगाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) से दो हजार रुपये से अधिक के वाणिज्यिक लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर)शुल्क लगाने के सरकार के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर आज केन्द्र, भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार के दो हजार रुपये से ज्यादा के लेनदेन के लिए जीरो-मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) वाली कानूनी सुरक्षा को वापस लेने के फैसले पर फिलहाल रोक नहीं लगाई है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने आज इस संबंध में एक याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम को नोटिस जारी करके यह बताने को कहा कि यूपीआई लेनदेन के लिए जीरो-मर्चेंट डिस्काउंट रेट वाली कानूनी सुरक्षा को वापस लेने का आधार क्या है।

आयकर विभाग ने कंपनियों के लिए कर ऑडिट रिपोर्ट, रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाई

● टैक्स ऑडिट वाले टैक्सपेयर्स के लिए आईटीआर की तारीख 21 नवंबर, ऑडिट रिपोर्ट की तारीख 21 हुई अक्टूबर

नई दिल्ली। आयकर विभाग ने कंपनियों को राहत देते हुए कर ऑडिट रिपोर्ट और आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समय-सीमा को बढ़ा दिया है।

आयकर विभाग ने सोमवार को 'एक्स' पोस्ट पर जारी बयान में बताया कि कंपनियों के लिए आकलन वर्ष 2026-27 का आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर से बढ़ाकर अब 21 नवंबर कर दिया गया है। साथ ही कर ऑडिट की रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख भी 30 सितंबर से बढ़ाकर 21 अक्टूबर कर दिया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बताया कि इनकम-टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (1) के 'एक्सप्लेनेशन 2 के तहत दी गई टेबल में क्रम संख्या 2 पर बताए गए लोगों के लिए आकलन वर्ष 2026-27 का इनकम रिटर्न जमा करने की आखिरी तारीख अब अक्टूबर, से बढ़ाकर 21 नवंबर, 2026 कर दी गई है। इसके अलावा ऐसे लोगों के लिए आकलन वर्ष 2026-27 के लिए इनकम-टैक्स एक्ट, 1961 के प्रावधानों के तहत ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की 'तय तारीख' को भी 21 अक्टूबर, 2026 तक बढ़ाई गई है। उल्लेखनीय है कि इस खबर में सबसे जरूरी बात दो तारीखों और दो कामों का फर्क है। 21 अक्टूबर तक ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी है, जबकि 21 नवंबर तक आईटीआर भरना है। ये दोनों काम एक नहीं हैं।

दिल्ली विंटर एक्शन प्लान तैयार, 'नो पीयूसीसी, नो फ्यूल' एक अक्टूबर से

नई दिल्ली,एजेंसी। दिल्ली में वायु प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सोमवार को पर्यावरण भवन में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा शामिल हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार ने एक व्यापक, रोकथाम-केंद्रित और समय-सीमा वाला 'विंटर एक्शन प्लान 2026-27' तैयार और इससे एक नंवबर से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई पूरी रणनीति 'संपूर्ण सरकार' और 'संपूर्ण समाज' के दृष्टिकोण पर आधारित है। इसके तहत केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, सीएक्यूएम, सीपीसीबी, स्थानीय निकायों, दिल्ली पुलिस, डीएमआरसी और अन्य संबंधित एजेंसियों को एक साथ लाया गया है। साथ ही, स्वच्छ हवा के लिए दिल्ली की इस लड़ाई के केंद्र में 'जन-भागीदारी' को प्रमुख आधार बनाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, इसके लिए हमारी सरकार बीते एक साल से एक विशेष और सुनियोजित रोडमैप पर काम कर रही है। जमीनी स्तर पर फैसलों को कड़ाई से लागू करने के साथ-साथ सभी एजेंसियों के समन्वय और अत्याधुनिक तकनीकों के उपयोग से स्थिति में बड़ा सुधार लाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने जनभागीदारी (हम सभी की जिम्मेदारी, साफ हवा में भागीदारी) के संकल्प के साथ 10-सूत्रीय कार्ययोजना और कड़े प्रतिबंधों की रूपरेखा पेश की और कहा कि हमारा यह प्लान दिल्ली में प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण लाएगा।

एक अक्टूबर से दिल्ली के सभी 500 ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर (एएनपीआर) युक्त पेट्रोल पंपों पर विशेष जागरूकता और प्रवर्तन अभियान शुरू किया जाएगा। बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र और मियाद पूरी कर चुके वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। शीतकालीन कार्ययोजना के तहत 1 नवंबर से दिल्ली के बाहर पंजीकृत और बीएस-ङ्कढ्ढ मानक से नीचे के सभी डीजल/पेट्रोल वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा (केवल सीएनजी और ईवी वाहनों को छूट)। 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक धूल उड़ाने वाली सभी तोड़फोड़ गतिविधियों और बाहरी सिविल निर्माण कार्यों पर पूर्ण रोक रहेगी। 10 दिसंबर से 20 जनवरी तक दिल्ली में सभी प्रकार के निर्माण और तोड़-फोड़ कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा। सभी निर्माण स्थलों पर 100 प्रतिशत सीसीटीवी कवरेज अनिवार्य होगी और नक्शा पास कराने के लिए 'मलबे ऐप' पर पंजीकरण जरूरी कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि एक नवंबर से विंटर प्रोटोकॉल के तहत सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम या सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम लागू रहेगा। यातायात का दबाव कम करने के लिए नगर निगम कार्यालयों (सुबह 8:30 से शाम 5:00) और दिल्ली सरकार के दफ्तरों (सुबह 10:00 से शाम 6:30) के समय में बदलाव किया गया है। निजी वाहनों के इस्तेमाल को घटाने के लिए दिल्ली में अधिकृत पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क दो गुना किया जाएगा (मेट्रो पार्किंग को छोड़कर)।

दिल्ली सरकार और आईसीसीआर के बीच एमओयू, सांस्कृतिक और शैक्षणिक सहयोग को मिलेगा बढ़ावा

सैफुल्लाह सिद्दीकी, वरिष्ठ पत्रकार

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की उपस्थिति में सोमवार को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) और दिल्ली सरकार के बीच सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस एमओयू का मुख्य उद्देश्य दिल्ली सरकार और आईसीसीआर के बीच संस्थागत साझेदारी स्थापित करना है, जिसके माध्यम से सांस्कृतिक और शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे दिल्ली की संस्कृति, पर्यटन और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ आईसीसीआर को सांस्कृतिक कूटनीति से जुड़े अपने दायित्वों को पूरा करने में भी सहयोग मिलेगा। इस अवसर पर दिल्ली के कला, संस्कृति एवं भाषा मंत्री कपिल मिश्रा कपिल मिश्रा सहित संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह साझेदारी दिल्ली की कला, संस्कृति और प्रतिभाओं को देश-दुनिया के व्यापक मंच से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे दिल्ली के कलाकारों और सांस्कृतिक समूहों को अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के अवसर मिलेंगे तथा विदेशी कलाकारों और सांस्कृतिक प्रतिनिधियों के माध्यम से दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक संवाद को भी बढ़ावा मिलेगा। आईसीसीआर के साथ यह संस्थागत साझेदारी दिल्ली की संस्कृति, पर्यटन और रचनात्मक अर्थव्यवस्था को नई गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस समझौते के अंतर्गत दिल्ली के स्थापित व युवा कलाकारों को आईसीसीआर की प्रतिष्ठित 'होराइजन सीरीज' और अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सवों में सहभागिता का सीधा अवसर मिलेगा। दिल्ली सरकार प्रदर्शन कला, साहित्य, मूर्तिकला, वस्त्र, वास्तुकला, पाक-कला और हस्तशिल्प जैसे विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें आईसीसीआर के साथ सूचीबद्ध करेगी। इन सभी विधाओं के कलाकारों की एक एकीकृत निर्देशिका (डायरेक्टरी) तैयार कर आईसीसीआर के साथ साझा की जाएगी, ताकि वैश्विक आयोजनों के लिए एक समृद्ध डेटाबेस उपलब्ध रहे। समझौते के तहत दिल्ली में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक एवं पर्यटन महोत्सवों में विदेशी कलाकारों की प्रस्तुतियों को सुगम बनाया जाएगा। आईसीसीसार के विशिष्ट आगंतुक कार्यक्रम और शैक्षणिक आगंतुक कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले विदेशी विशिष्ट अतिथियों व विद्वानों की मेजबानी दिल्ली में की जाएगी। इसके अतिरिक्त, भारत और विदेशों के विजुअल आर्टिस्ट के लिए संयुक्त कला प्रदर्शनी, आर्टिस्ट रेजीडेंसी कैंप, वर्कशॉप और सेमिनार आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही भारत और विदेशों के दृश्य कलाकारों के लिए ग्रुप एग्जीबिशन, आर्टिस्ट रेजिडेंसी कैंप, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार और वर्कशॉप आयोजित किए जा सकेंगे। आईसीसीसार से जुड़े विदेशी छात्रों के लिए दिल्ली में अध्ययन शिविर और परिचयात्मक दौरों का आयोजन किया जाएगा, जिससे राजधानी के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, आईसीसीआर के अंतरराष्ट्रीय छात्र नेटवर्क के बीच दिल्ली के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। इस एमओयू के अंतर्गत दिल्ली में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक दलों की भागीदारी के लिए आवश्यक खर्च दिल्ली सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। वहीं, आईसीसीआर अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों की पहचान, वीजा और भारत यात्रा से संबंधित आवश्यक व्यवस्थाओं में सहयोग करेगा। विदेशों में आयोजित कार्यक्रमों में दिल्ली के कलाकारों एवं सांस्कृतिक दलों की भागीदारी के लिए घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, परिवहन, वीजा और आवश्यक सरकारी मंजूरियों से जुड़े खर्च दिल्ली सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे। आईसीसीआर की ओर से कलाकारों के अंतरराष्ट्रीय प्रवास, प्रस्तुतियों, प्रचार-प्रसार और चिकित्सा संबंधी व्यवस्थाओं में सहयोग किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने दिल्ली उद्योग मित्र पोर्टल का किया शुभारंभ

शाहनवाज सैफ, सद्भावना टुडे

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को दिल्ली सचिवालय में सेवा संकल्प अभियान के तहत 'दिल्ली उद्योग मित्र पोर्टल' का शुभारंभ किया। यह पोर्टल दिल्ली में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इकोसिस्टम को मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार किया गया एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसके जरिए उद्यमियों, व्यापारियों, एमएसएमई, स्टार्टअप्स, औद्योगिक इकाइयों और निवेशकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं एवं अनुमतियों तक एक ही डिजिटल इंटरफेस के माध्यम से आसान पहुंच मिल सकेगी। इस अवसर पर दिल्ली के उद्योग मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

'दिल्ली उद्योग मित्र पोर्टल' पर वर्तमान में 15 विभागों की 50 से अधिक सरकारी सेवाएं एकीकृत की गई हैं। सरकार का लक्ष्य इसे बढ़ाकर 21 विभागों की 100 से अधिक सेवाओं तक करना है। इससे दिल्ली के 8 लाख से अधिक व्यापारियों, जिनमें एमएसएमई भी शामिल हैं, को सरकारी सेवाओं तक आसान और सुविधाजनक पहुंच मिलने की उम्मीद है। पोर्टल को नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस) के साथ भी एकीकृत किया गया है। इसके माध्यम से निवेशकों और कारोबारियों को केंद्र तथा राज्य स्तर की अनुमतियों तक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म से पहुंच मिल सकेगी। इससे मंजूरियों की प्रक्रिया को अधिक तेज और पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी। 'दिल्ली उद्योग मित्र पोर्टल' आवेदकों को अनुमतियों की पहचान करने, आवेदन जमा करने, आवेदन की स्थिति देखने और विभिन्न विभागों के साथ एक ही डिजिटल इंटरफेस के माध्यम से संवाद करने की सुविधा प्रदान करेगा। पोर्टल में कई महत्वपूर्ण डिजिटल सुविधाएं शामिल की गई हैं। सिंगल साइन-ऑन (एसएसओ) के माध्यम से एक ही लॉगिन से विभिन्न विभागों की सेवाओं तक पहुंच मिल सकेगी। वहीं कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म (सीएएफ) के माध्यम से आवेदकों को बार-बार एक जैसी मूलभूत जानकारी जमा करने की आवश्यकता कम होगी। 'नो योर अप्रूवल्स' (केवाईए) सुविधा उद्यमियों को उनके प्रस्तावित व्यवसाय के लिए आवश्यक अनुमतियों की जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगी। आवेदक डैशबोर्ड के माध्यम से आवेदन की स्थिति एक ही स्थान पर देखी जा सकेगी, जबकि विभागीय डैशबोर्ड संबंधित विभागों को आवेदनों और सेवा वितरण की निगरानी में सहायता करेगा। इसके साथ ही गाइडेंस मॉड्यूल के माध्यम से प्रश्नोत्तर, मैनुअल और सेवाओं से संबंधित मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि आवेदन करने से पहले ही उद्यमियों को आवश्यक प्रक्रिया की स्पष्ट जानकारी मिल सके।

महिला सुरक्षा को लेकर 'चलो डीयू : मार्च फॉर विमेन सेफ्टी' को डूसू का समर्थन

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय में महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों की अपील पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) द्वारा आयोजित किए जा रहे 'चलो डीयू : मार्च फॉर विमेन सेफ्टी' को अभाविप-नीत दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) ने समर्थन दिया है। हाल के दिनों में महिला सुरक्षा से जुड़े घटनाक्रमों के बाद विद्यार्थियों के बीच सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ अध्यक्ष यश डबास ने मार्च का समर्थन करते हुए कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रत्येक छात्रा को सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि परिसर के साथ-साथ छात्राओं के आवागमन वाले क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता है। डूसू अध्यक्ष ने कहा कि महिला विद्यार्थियों की सुरक्षा विश्वविद्यालय की प्राथमिकताओं में शामिल होनी चाहिए। उन्होंने परिसर और आसपास के क्षेत्रों में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, सीसी उनके अनुसार, विश्वविद्यालय प्रशासन और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से विद्यार्थियों की सुरक्षा संबंधी चिंताओं का प्रभावी समाधान किया जाना चाहिए। डूसू सचिव रिया छावड़ी ने कहा कि महिला विद्यार्थियों की सुरक्षा विश्वविद्यालय की प्राथमिकताओं में शामिल होनी चाहिए। उन्होंने परिसर और आसपास के क्षेत्रों में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों, नियमित सुरक्षा गश्त और शिकायतों के त्वरित निवारण की व्यवस्था सुनिश्चित करने की आवश्यकता बताई।

एसआईआर को लेकर विपक्ष पर महापौर प्रवेश वाही का हमला

नई दिल्ली। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर आम आदमी पार्टी (आआपा) और कांग्रेस पर भारत निर्वाचन आयोग की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल पहले ईवीएम के नाम पर चुनाव आयोग को निशाना बनाते थे और अब एसआईआर को मुद्दा बनाकर संवैधानिक संस्था की प्रतिष्ठा प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं।

महापौर प्रवेश वाही ने उपमहापौर डॉ. मोनिका पंत की मौजूदगी में सोमवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि आआपा नेता अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा संवैधानिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा पर सवाल उठाना कोई नई बात नहीं है। वाही ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल के दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते दिल्ली नगर निगम के फंड रोककर उसकी कार्यप्रणाली को प्रभावित करने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में निगम चुनाव के बाद भी करीब दो वर्ष तक नगर निगम का संवैधानिक गठन नहीं होने दिया गया, जिससे निगम की स्वायत्तता प्रभावित हुई। महापौर और उपमहापौर ने संयुक्त बयान में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आज एसआईआर को लोकतंत्र के लिए खतरा बताने वाले कांग्रेस नेताओं को आपातकाल के दौर को भी याद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश लोकतंत्र से जुड़े उस दौर की घटनाओं को नहीं भूला है। वाही ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम से लेकर विधानसभा चुनावों तक विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने के लिए अलग-अलग मुद्दे उठाए हैं। उन्होंने दावा किया कि अब एसआईआर को भी इसी उद्देश्य से मुद्दा बनाया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर चुनाव आयोग से जुड़े पुराने घटनाक्रमों को लेकर भी निशाना साधा। वाही ने कहा कि देश उन घटनाओं को नहीं भूला है, जिनमें पूर्व चुनाव आयुक्त एसएल शकधर और एमएस गिल को लेकर कांग्रेस पर पक्षपात के आरोप लगाए गए, जबकि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन के साथ

एमसीडी का शहरव्यापी प्रवर्तन अभियान जारी, 29 ध्वस्तीकरण कार्रवाई

सद्भावना टुडे, संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने अनधिकृत निर्माण, खतरनाक भवनों तथा दिल्ली के मास्टर प्लान (एमपीडी) और भवन उपनियमों के उल्लंघन के खिलाफ शहरव्यापी प्रवर्तन अभियान जारी रखा है। निगम के सभी 12 जोनों में भवन मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने और जनसुरक्षा बनाए रखने के लिए कार्रवाई की जा रही है। अभियान के तहत सोमवार को दिल्ली के सभी 12 जोनों में 29 ध्वस्तीकरण कार्रवाई की गईं। इसके अलावा 10 संपत्तियों को सील किया गया तथा 7 ध्वस्तीकरण आदेश जारी किए गए। एमसीडी के अनुसार, उसके क्षेत्राधिकार में भवन निर्माण संबंधी नियमों के उल्लंघन पर निर्धारित नियमों और विनियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है।

प्रवर्तन अभियान के दौरान हरि नगर, टैगोर गार्डन एक्सटेंशन, विकासपुरी, डाबरी मोड़, सीतापुरी, रेघड़पुरा, देव नगर, शारदा पुरी, केशवपुरम, कपिल विहार, शकरपुर, कैलाश नगर, गांधी नगर, मधु विहार, पश्चिम विनोद नगर, पुरानी सीमापुरी, चौहान बांगर, बामनौली, कादीपुर, केशव नगर और इब्राहिमपुर सहित दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में ध्वस्तीकरण कार्रवाई की गई। एमसीडी ने स्पष्ट किया कि उसके क्षेत्राधिकार में अनधिकृत निर्माण और भवन मानदंडों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निगम के फील्ड अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित निगरानी बनाए रखें और एमपीडी, भवन उपनियमों तथा अन्य संबंधित नियमों के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। निगम के मुताबिक, यह प्रवर्तन अभियान सभी 12 जोनों में लगातार जारी रहेगा। अनधिकृत निर्माण, खतरनाक भवनों तथा जनसुरक्षा के लिए जोखिम पैदा करने वाले अन्य उल्लंघनों की पहचान कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

उप-महापौर ने गिरधर लाल अस्पताल का किया निरीक्षण

शबाना बेगम, सद्भावना टुडे

नई दिल्ली। दिल्ली की उप-महापौर डॉ. मोनिका पंत ने सोमवार को गिरधर लाल अस्पताल का विस्तृत निरीक्षण कर अस्पताल में मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं, दवाओं की उपलब्धता, स्वच्छता व्यवस्था तथा चिकित्सा एवं सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल प्रशासन को मरीजों की सुविधा एवं बेहतर उपचार व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उप-महापौर ने अस्पताल के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण करते हुए स्वच्छता व्यवस्था को प्राथमिकता देने तथा अस्पताल परिसर में साफ-सफाई के उच्च मानकों को लगातार बनाए रखने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उप-महापौर ने बताया कि मरीजों को आधुनिक एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अस्पताल में शीघ्र ही आधुनिक तकनीक पर आधारित नई चिकित्सा मशीनें एवं उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। इसी दिशा में अस्पताल में डायलिसिस मशीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि मरीजों की आवश्यकताओं के अनुरूप अन्य आवश्यक चिकित्सा उपकरण भी चरणबद्ध तरीके से अस्पताल में उपलब्ध कराए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि अस्पताल के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर एवं सुदृढ़ बनाने के लिए लगभग चार करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। इस राशि के माध्यम से अस्पताल की आधारभूत सुविधाओं में आवश्यक सुधार किए जाएंगे, जिससे मरीजों और उनके साथ आने वाले परिजनों को अधिक सुविधाजनक एवं बेहतर वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। डॉ. मोनिका पंत ने अस्पताल में उपचार करा रहे मरीजों एवं उनके परिजनों से भी संवाद किया। उन्होंने मरीजों से अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं, दवाओं की उपलब्धता तथा उन्हें प्रदान किए जा रहे उपचार के संबंध में जानकारी ली और उनकी समस्याओं को सुना। उप-महापौर ने जानकारी दी कि अस्पताल में मरीजों को सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जल्द ही जन औषधि स्टोर खोले जाने की योजना है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ दवाओं की सहज उपलब्धता भी मरीज-केंद्रित स्वास्थ्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिया कि मरीजों की आवश्यकताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए तथा अस्पताल में स्वच्छता, दवा उपलब्धता और उपचार संबंधी व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा की जाए। निरीक्षण के दौरान स्थानीय पार्षद किरण बाला, अतिरिक्त आयुक्त पंकज नरेश अग्रवाल, निदेशक अस्पताल प्रशासन डॉ ए एन माथुर, चिकित्सा अधीक्षक डॉ सत्य प्रकाश सहित अस्पताल एवं निगम के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

रोहिणी के फाइनेंसर से मांगी एक करोड़ की रंगदारी, दो पिस्टल और 14 कारतूस के साथ बदमाश गिरफ्तार

नई दिल्ली। रोहिणी के एक फाइनेंसर से एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने और रकम नहीं देने पर उसकी हत्या की साजिश रचने के आरोप में क्राइम ब्रांच ने अंतरराज्यीय बदमाश हरेंद्र नागर उर्फ केडी (33) को गिरफ्तार किया है। आरोपित के पास से दो अत्याधुनिक अवैध पिस्टल और 14 कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपित का संबंध भाऊ गैंग से है। जांच में वह हरियाणा के अंबाला में 18 अगस्त को वैन से करीब 1.5 किलो सोने के आभूषण लूटने के मामले में भी वांछित मिला है। क्राइम ब्रांच की वेस्टर्न रेंज-1 की टीम को नौ सितंबर को सूचना मिली थी कि हरेंद्र ने रोहिणी सेक्टर-7 निवासी फाइनेंसर अजय यादव उर्फ बॉस को धमकी देकर एक करोड़ रुपये की प्रोटेक्शन मनी मांगी है। रकम देने से इन्कार करने के बाद वह फाइनेंसर की हत्या के इरादे से दिल्ली आया है। सूचना पर इंस्पेक्टर प्रकाश चंद के नेतृत्व में एसआई सुमित, हेड कांस्टेबल रामबीर, नवीन और विनोद की टीम बनाई गई। एसीपी राजकुमार की निगरानी और डीसीपी क्राइम ब्रांच हर्ष इंदौरा के निर्देशन में टीम ने तकनीकी निगरानी शुरू की।

पुख्ता सूचना के बाद टीम ने रोहिणी सेक्टर-24 में नाले के पास घेराबंदी की। रात करीब 10:45 बजे मुखबिर की निशानदेही पर हरेंद्र को दबोच लिया गया। तलाशी के दौरान आरोपित की जींस की जेब से एक अवैध पिस्टल और पांच कारतूस मिले। बैग से दूसरी पिस्टल और चार कारतूस बरामद हुए, जबकि पांच अन्य कारतूस भी उसके कब्जे से मिले। कुल दो पिस्टल और 14 कारतूस बरामद किए गए। इस संबंध में क्राइम ब्रांच थाने में आर्म्स एक्ट की धाराओं में एफआईआर नंबर 217/26 दर्ज की गई। पूछताछ में पुलिस के अनुसार हरेंद्र ने बताया कि उसने साथी दीपक के साथ मिलकर अजय यादव से एक करोड़ रुपये वसूलने की साजिश रची थी।

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली कांग्रेस का प्रदर्शन, सैकड़ों कार्यकर्ता हिरासत में

सद्भावना टुडे, संवाददाता

नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में सोमवार को हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग की ओर कूच करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक दिया। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव सहित सैकड़ों नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ता 'ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो', 'वोट चोर गद्दी छोड़ो' सहित विभिन्न नारे लगा रहे थे। कांग्रेस नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की भी मांग की। देवेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी द्वारा उठाए गए कथित 'वोट चोरी' के मुद्दे को लेकर एकजुट हैं। उन्होंने कहा कि जब तक ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते, तब तक कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और दिल्ली के सभी जिलों तथा ब्लॉकों में इस्तीफे की मांग को लेकर अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इसके बाद देशभर में घर-घर जाकर इस मुद्दे को उठाया जाएगा। देवेंद्र यादव ने दावा किया कि तीन दिनों के भीतर दूसरी बार दिल्ली कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता इस मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से कार्यकर्ता चुनाव आयोग की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोककर हिरासत में ले लिया।

एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस के आरोप

देवेंद्र यादव ने एसआईआर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा लिए गए कुछ निर्णयों को लेकर अन्य चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों ने कांग्रेस द्वारा उठाए गए सवालों को और गंभीर बना दिया है। उन्होंने दावा किया कि पिछले डेढ़-दो वर्षों में कई नागरिकों ने मतदान के दौरान अपना नाम मतदाता सूची में नहीं होने या किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित होने की शिकायत की है।

उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठाती रही है और इसे लोकतांत्रिक अधिकारों से जोड़कर देखती है। हालांकि, ये आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए गए हैं और इनके संबंध में संबंधित संवैधानिक संस्थाओं का पक्ष अलग हो सकता है। देवेंद्र यादव ने कहा कि राहुल गांधी ने करीब दो वर्ष पहले कथित वोट चोरी का मुद्दा उठाया था और कांग्रेस इस मुद्दे पर अपनी लड़ाई जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस की कार्रवाई के बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ता पीछे नहीं हटेंगे।

काजी निजामुद्दीन ने भी उठाए सवाल

दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी काजी निजामुद्दीन ने कहा कि कांग्रेस और देश 'वोट चोरी' को स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी द्वारा उठाए गए सवालों के संदर्भ में चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेदों को गंभीरता से देखा जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। काजी निजामुद्दीन ने कहा कि ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस का आंदोलन अब व्यापक रूप ले चुका है और पार्टी कार्यकर्ता इस मुद्दे पर अपना विरोध जारी रखेंगे।

कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता रहे मौजूद

प्रदर्शन में देवेंद्र यादव के साथ कांग्रेस के दिल्ली प्रभारी काजी निजामुद्दीन, सचिव प्रभारी दानिश अबरार, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अल्का लांबा, पूर्व सांसद रमेश कुमार, उदित राज, कृष्णा तीरथ, दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री हारून यूसुफ, नरेंद्र नाथ, प्रदेश महासचिव संगठन एवं पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज, पूर्व विधायक भीष्म शर्मा, विजय लोचव, हरी शंकर गुप्ता, आसिफ मोहम्मद खान, सुरेंद्र कुमार, तस्वीर सोलंकी, जगजीवन शर्मा, कमल कांत शर्मा, मुदित अग्रवाल, अली मेंहदी, राजिंदर तंवर, धर्मपाल चंदेला, गौरी शंकर शर्मा, सतेंद्र शर्मा, डॉ. पी.के. मिश्रा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शन में महिला कांग्रेस, सेवा दल, लीगल सेल, सोशल मीडिया विभाग, बूथ कमेटी तथा विभिन्न जिला कांग्रेस इकाइयों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल हुए।

शरजील इमाम मामले में हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से चार हफ्ते में मांगा जवाब

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली हिंसा की साजिश रचने के आरोपित शरजील इमाम की जेल के अंदर पीएचडी शोध के लिए शोध सामग्री एक्सेस करने और जेल के कंप्यूटर का इस्तेमाल करने की अनुमति देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। जस्टिस संजीव नरुला की पीठ ने दिल्ली पुलिस को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी। सुनवाई के दौरान शरजील इमाम की ओर से पेश वकील अहमद इब्राहिम ने कहा कि शरजील की गिरफ्तारी जनवरी, 2020 में हुई थी और उसकी गिरफ्तारी के समय वो पीएचडी के अंतिम वर्ष में था। यूजीसी और जेएनयू ने शरजील की सिनॉप्सिस को स्वीकृत भी कर दिया था। उन्होंने कहा कि शरजील इमाम को पेन ड्राइव में अपनी शोध सामग्री देखने की अनुमति दी जाए। तब कोर्ट ने पूछा कि वो शोध सामग्री की फिजिकल प्रति क्यों नहीं लेना चाह रहे हैं, तब इब्राहिम ने कहा कि वो लाखों पेज में हैं। इब्राहिम ने कहा कि वे जेल के अंदर इंटरनेट के इस्तेमाल की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे बिना इंटरनेट का कंप्यूटर चाहते हैं जिस पर वे अपनी शोध सामग्री देख सकें।

शरजील इमाम की याचिका में कहा गया है कि अप्रैल, 2026 में ट्रायल कोर्ट ने जेल अधीक्षक को निर्देश दिया था कि वो इस मांग पर विचार करें। तत्कालीन जेल अधीक्षक ने अपने वकील के जरिये शरजील को पेन ड्राइव में शोध सामग्री उपलब्ध कराने की अनुमति दे दी थी, लेकिन जेल अधीक्षक का ट्रांसफर हो गया और उनकी जगह आए जेल अधीक्षक ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। शरजील इमाम को 2020 में बिहार से गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली दंगों में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे।

एक नजर

गुरुग्राम में युवक ने ट्रेन से कटकर दी जान, 10 मीटर दूर जाकर गिरी गर्दन

गुरुग्राम। सोमवार को यहां एक 29 वर्षीय युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। हादसा इतना भयावह था कि युवक की गर्दन धड़ से अलग होकर करीब 10 मीटर दूर जा गिरी। सूचना मिलते ही राजकीय रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। मृतक की पहचान राजेंद्र पार्क निवासी मोहित (29) के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार मोहित अविवाहित था और नौकरी की तलाश में गुरुग्राम आया था। उसने तीन दिन पहले ही दौलताबाद फ्लाईओवर के पास स्थित एक मेगा मॉल में नई नौकरी शुरू की थी। बताया जा रहा है कि सोमवार को मोहित अचानक रेलवे ट्रैक पर पहुंचा और आती ट्रेन के सामने कूद गया। ट्रेन की चपेट में आने से उसका शव क्षत-विक्षत हो गया। घटना की सूचना स्टेशन मास्टर ने तुरंत राजकीय रेलवे पुलिस को दी। जांच अधिकारी बाबूलाल और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम मौके पर पहुंची और ट्रैक पर बिखरे शव के हिस्सों को एकत्र कर नागरिक अस्पताल के शवगृह में पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया। जांच अधिकारी बाबूलाल ने बताया कि मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है, जिससे आत्महत्या के कारणों का पता चल सके। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच का दायरा बढ़ा दिया है। मोहित के मोबाइल की कॉल डिटेल, मैसेज और उसके निजी व पेशेवर जीवन से जुड़े पहलुओं की जांच की जा रही है। उसके परिजनों और दोस्तों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। युवक की मौत की खबर मिलते ही राजेंद्र पार्क स्थित उसके घर में मातम पसर गया।

वर्तमान में शहीद-ए-आजम के विचारों की बहुत जरूरतः राजेंद्र पाठक

गुरुग्राम। ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन गुरुग्राम इकाई द्वारा सोमवार को शहीद-ए-आजम भगत सिंह की 120वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने भगत सिंह के विचारों को आज के दौर में प्रासंगिक बताया। कार्यक्रम में ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन गुरुग्राम के अध्यक्ष एडवोकेट राजेंद्र पाठक ने कहा कि आज के दौर में शहीद-ए-आजम के विचारों की बहुत जरूरत है। उन्होंने कहा कि यह शहीद-ए-आजम भगत सिंह का भारत नहीं है। भगत सिंह ने समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, सबको काम, भाईचारा और बराबरी का सपना देखा था। उन्होंने कहा कि हमें आज खुद से यह वादा करना होगा कि हम भगत सिंह के सपनों को साकार करेंगे। राजेंद्र पाठक ने कहा कि शहीद-ए-आजम सरदार भगत सिंह भारत के सबसे महान और प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को बंगा, लायलपुर (अब पाकिस्तान) में हुआ था। जलियांवाला बाग की घटना, क्रांतिकारी संगठनों से जुड़ाव, समाजवादी विचारों की ओर बढ़ता रुझान, जेल और भूख हड़ताल जैसे पड़ावों ने उनके जीवन की दिशा तय की और वे आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। भगत सिंह जब करीब 12 साल के थे, तब जनरल डायर की गोलीबारी के बाद वे अमृतसर पहुंचे। उन्होंने जलियांवाला बाग जाकर वहां की खून से सनी मिट्टी अपने साथ ली और देश को आजाद कराने की कसम खाई। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट विनोद भारद्वाज ने कहा कि देश की आजादी के लिए सरदार भगत सिंह ने मात्र 23 वर्ष की उम्र में 23 मार्च 1931 को हंसते-हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। नौजवान भारत सभा और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना व संचालन। लाल लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सांडर्स को मारा। आठ अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर भरी सेंट्रल असेम्बली में पर्चे फेंके और बम धमाका किया जिसका उद्देश्य किसी को मारना नहीं बल्कि बहरों को अपनी आवाज सुनाना था। इस कार्यक्रम में एडवोकेट आरके तंवर, एसएस डागर, महेंद्र सिंह, ज्योति शर्मा, कुलदीप शर्मा, एसएस हुड्डा, पटेल सहित कई अधिवक्ताओं ने हिस्सा लिया और शहीद भगत सिंह को याद किया।

गुरुग्राम में जैन समाज ने श्रद्धा एवं संयम के साथ मनाया पर्वाधिराज दशलक्षण महापर्व

गुरुग्राम। जैन धर्म के सबसे पवित्र पर्व, पर्वाधिराज दशलक्षण महापर्व गुरुग्राम के जैकबपुरा स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में त्याग, तपस्या, संयम और साधना के साथ मनाया गया। दशलक्षण पर्व का समापन क्षमावाणी महापर्व के रूप में किया गया। सभी जैन बंधुओं ने एक-दूसरे से मिच्छामि दुक्कड़म्-उत्तम क्षमा कहकर जाने-अनजाने हुई भूलों के लिए क्षमा याचना की गई। मंगलवार की सुबह कार्यक्रम में हरियाणा मानवाधिकार आयोग के सदस्य कुलदीप जैन ने शिरकत की। उन्होंने रथ यात्रा में उपस्थित होकर भगवान का आशीर्वाद लिया। मंदिर प्रबंधन कमेटी के अनुसार दशलक्षण महापर्व के दस दिन आत्मशुद्धि के दस धर्मों-उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य के प्रतीक हैं। इन दस दिनों में श्रद्धालु व्रत, उपवास, स्वाध्याय और प्रवचनों के माध्यम से अपने जीवन को संयमित करने का प्रयास करते हैं। प्रतिदिन प्रातःकालीन अभिषेक, शांतिधारा और भक्ति के बाद विद्वानों द्वारा दशलक्षण धर्म पर प्रवचन आयोजित किए गए। सायंकाल में सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन संध्या और तत्व चर्चा का आयोजन हुआ।

नगर निगम ने पांच हजार पशु पकड़े, फिर भी सड़कें नहीं हुई खाली

फरीदाबाद,एजेंसी। फरीदाबाद में सड़कों पर घूमने वाले बेसहारा पशुओं को अब दूसरे जिलों की गौशालाओं में भेजा जाएगा। नगर निगम का कहना है कि शहर की तीनों गौशालाओं में पहले ही क्षमता से अधिक पशु रखे हुए हैं। ऐसे में अब पड़ोसी जिलों की गौशालाओं में पशुओं को भेजने की तैयारी की जा रही है। इसकी शुरुआत नूंह की गोशाला से किए जाने की योजना है। शहर में बेसहारा पशुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए नगर निगम ने रोजाना निगरानी की व्यवस्था की है। निगम कमिश्नर यशेंद्र सिंह ने पांचों जोन के ज्वाइंट कमिश्नरों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है।

ज्वाइंट कमिश्नर प्रतिदिन स्वास्थ्य शाखा से रिपोर्ट लेंगे। इसमें यह जानकारी ली जाएगी कि दिनभर में कितने पशुओं को सडक़ों से पकड़ा गया और कितने पशुओं को गोशाला तक पहुंचाया गया। निगम से मिली जानकारी के अनुसार अभी तक 2 साल में अवारा पशुओं से कारण हुए हादसे में 15 लोग घायल हुए है जबकि 6 लोगों की मौत

हो चुकी है। दावा है कि कि वर्ष 2024 से वर्ष 2026 के बीच करीब पांच हजार लावारिस पशुओं को पकडक़र विभिन्न गौशालाओं में छोड़ा गया। इनमें सबसे ज्यादा 2044 पशु श्री गोपाल गोशाला में, 1739 गो रक्षा सदन मवई में और 578 गो मानव सेवा ट्रस्ट में रखे गए हैं। इसके अलावा देवाश्रय एनिमल हॉस्पिटल में 52, छांयसा गोशाला में 43 और नवादा गोशाला में 319 पशु भेजे गए। इसके बावजूद शहर की सडक़ों पर पशुओं की संख्या कम होने के बजाय बढ़ती ही नजर आ रही है। निगम की ओर से यह भी जानकारी जुटाई जाएगी कि सडक़ों पर पशु छोडऩे वाले कितने लोगों के खिलाफ जुर्माना लगाया गया। अधिकारियों को पशुओं को सडक़ से हटाने के साथ-साथ उनके मालिकों पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। निगम का उद्देश्य शहर की मुख्य सडक़ों और रिहायशी क्षेत्रों में बेसहारा पशुओं की संख्या को कम करना है।

औद्योगिक नगरी में सडक़ों पर घूमने वाले पशु वाहन चालकों के लिए परेशानी का कारण बने हुए हैं। रात के समय सडक़ पर बैठे पशु दिखाई नहीं देने से हादसे का खतरा और बढ़ जाता है। करीब दो सप्ताह पहले अंधेरे में सडक़ पर बैठी गाय बाइक सवार को दिखाई नहीं दी थी। बाइक के गाय से टकराने के बाद हादसे में उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद निगम की कार्रवाई पर भी सवाल उठे थे। फरीदाबाद में नगर निगम की निगरानी में तीन गौशालाएं हैं। निगम की ओर से इन गौशालाओं को फंड भी दिया जाता है। हालांकि, अधिकारियों के अनुसार तीनों गौशालाओं में उनकी क्षमता से अधिक पशु पहले से मौजूद हैं। इसी वजह से अब पशुओं को दूसरे जिलों की गौशालाओं में भेजने का विकल्प अपनाया जा रहा है। नगर निगमकमिश्नर यशेंद्र सिंह ने बताया कि सडक़ों से बेसहारा पशुओं को हटाने की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

सातवीं कक्षा की छात्रा ने दसवीं मंजिल से कूदकर की आत्महत्या

गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद क्षेत्र के एक सोसाइटी में रहने वाली सातवीं कक्षा की छात्रा ने बीती रात दसवीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर लिया। छात्रा राजेंद्र नगर के एक नामी स्कूल में पढ़ती थी। छात्रा ने अपनी पर्सनल डायरी में शिक्षिका द्वारा प्रताड़ित करने की बात लिखी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सहायक पुलिस आयुक्त साहिबाबाद अमित सक्सेना ने बताया कि थाना साहिबाबाद क्षेत्र में रहने वाली रितिका (12) सातवीं कक्षा की छात्रा ने बीती रात को अपनी सोसाइटी की दसवीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर लिया है। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि छात्रा शनिवार रात को घर से यह कहकर निकली थी कि वह पड़ोसियों के यहां जा रही है ,लेकिन उसने दसवीं मंजिल पर जाकर नीचे छलांग लगा दिया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उन्होंने बताया कि मृतका के परिजनों का कहना है कि हाल ही में उसके स्कूल में इंटरनल एग्जाम हुए थे। सभी छात्रों को उसकी कॉपी दी गई थी। छात्रा के मैथन मे 30 नंबर आए थे। नंबर देखकर उसने सहपाठी से टीचर की हालत खराब करने की बात कही थी। उसने पर्सनल डायरी का भी जिक्र किया। उसके बाद परिजन ने उसकी डायरी चेक की। उन्होंने बताया कि छात्रा ने अपनी एक स्कूल डायरी को पर्सनल डायरी बनाया हुआ था। वह डायरी किसी को पढ़ने नहीं देती थी। छात्रा के पिता के अनुसार छात्रा ने उसमें अपनी आपबीती लिखी थी। जिस पर एक पेज पर उसने टीचर के उत्पीड़न की बात लिखी है।

नूंह में भाजपा नेता जाहिद हुसैन को धमकी देकर मांगे पांच करोड़

नूंह। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एवं नूंह के पूर्व चेयरमैन जाहिद हुसैन को कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई और गौदारा गैंग के नाम पर जान से मारने की धमकी देते हुए 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। धमकी भरे फोन के बाद जाहिद हुसैन ने नूंह पुलिस अधीक्षक डॉ. अर्पित जैन को शिकायत देकर अपने और परिवार की सुरक्षा तथा आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

शिकायत के अनुसार, 27 सितंबर 2026 की रात जाहिद हुसैन के मोबाइल फोन पर 9520250016 नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को गौदारा गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताते हुए धमकी दी। शिकायतकर्ता के मुताबिक, फोन करने वाले ने कहा कि वह भारतीय जनता पार्टी में बड़ा नेता है और यदि उसे अपनी तथा अपने बच्चों की जान प्यारी है तो दो दिन के अंदर 5 करोड़ रुपये देने होंगे। साथ ही धमकी देने वाले ने दावा किया कि उसके पास जाहिद हुसैन और उनके परिवार की पूरी जानकारी है। शिकायत में बताया गया है कि फोन करने वाले ने कहा कि उसका बॉस जाहिद हुसैन से बात करना चाहता है और यदि बॉस से बात नहीं की तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। इस पर जाहिद हुसैन ने कहा कि वह मौत से नहीं डरते, जिसके बाद फोन काट दिया गया। इसके करीब पांच मिनट बाद रात 8 बजकर 23 मिनट पर उसी मोबाइल नंबर से दोबारा कॉल आने का भी शिकायत में उल्लेख है। आरोप है कि इस दौरान फोन करने वाले ने कथित तौर पर 'हां या ना' में जवाब देने को कहा और पैसे नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी। जाहिद हुसैन ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि वह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं और गांव बाई, हालाबाद, गऊशाला रोड, थाना सिटी नूंह के स्थायी निवासी हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें लॉरेंस गैंग के नाम पर 5 करोड़ रुपये की फिरौती के लिए धमकी दी गई है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से अपने और अपने परिवार की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। शिकायत मिलने के बाद नूंह पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस की ओर से धमकी देने के लिए इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर की जांच की जा रही है। कॉल करने वाले व्यक्ति की पहचान और धमकी के पीछे की वास्तविकता का पता लगाने के लिए पुलिस विभिन्न पहलुओं से मामले की जांच कर रही है।

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में छाया यूपी स्टार्टअप मिशन

अशोक कुमार, सद्भावना टुडे

नोएडा। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो-26 (यूपीआईटीएस-26) में उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन के पवेलियन में प्रदेश के उभरते स्टार्टअप्स के नवाचार आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। स्टार्टअप मिशन के बैनर तले विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 60 स्टार्टअप्स ने अपने उत्पाद, तकनीक और नवाचार प्रदर्शित किए हैं। पिछले तीन दिनों में 5000 से अधिक विजिटर्स स्टार्टअप पवेलियन का दौरा कर चुके हैं। पवेलियन में आईटी-आईटीईएस, हेल्थटेक, एडटेक, कृषि, डीपटेक और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अलग-अलग क्षेत्रों में काम कर रहे स्टार्टअप्स की भागीदारी देखने को मिल रही है। यूपी स्टार्टअप मिशन सीईओ सुमित महाजन ने बताया कि यूपीआईटीएस-26 के पवेलियन में 60 स्टार्टअप्स ने प्रतिभाग किया है।

इनमें आईटी और आईटीईएस, हेल्थटेक, एडटेक, कृषि, डीपटेक और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र प्रमुख हैं। अलग-अलग सेक्टर से आए स्टार्टअप्स ने अपने उत्पादों और तकनीकी समाधानों को प्रदर्शित किया है। वहीं स्टार्टअप पवेलियन को देखने के लिए विजिटर्स की भी अच्छी संख्या पहुंच रही है। पिछले तीन दिनों में 5000 से अधिक लोग पवेलियन का दौरा कर चुके हैं। विजिटर्स ने स्टार्टअप्स के उत्पादों, तकनीकी समाधानों और नवाचारों को देखा तथा

उनके बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने बताया कि यूपी स्टार्टअप मिशन के पवेलियन में भारत इनोवेट्स के लिए चयनित छह स्टार्टअप्स ने भी भागीदारी की है। इन स्टार्टअप्स ने ट्रेड शो में अपने नवाचारों को प्रदर्शित किया। इसके अलावा यूपी स्टार्टअप फंड से वित्त पोषित छह स्टार्टअप्स ने भी पवेलियन में अपने उत्पाद और नवाचार पेश किए हैं।

स्टार्टअप पवेलियन में एलएंडटी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के सीईओ संदीप कुमार ने भी स्टार्टअप्स के फाउंडर्स से संवाद किया। उन्होंने स्टार्टअप्स के काम और उनके नवाचारों के बारे में जानकारी ली। संवाद सत्र के दौरान उन्होंने स्टार्टअप फाउंडर्स को प्रोत्साहित किया और उनके प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। सीईओ सुमित महाजन ने बताया कि ट्रेड शो में रक्षा तकनीक और डीपटेक से जुड़े नवाचार भी आकर्षण का केंद्र बने हैं। इनमें आईआईटी कानपुर की डीपटेक स्टार्टअप मराल एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड का सौर ऊर्जा से संचालित अल्ट्रा लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी 'तेजस्वान' खास है। यह फिक्स्ड विंग विमान सौर ऊर्जा और बैटरी के संयोजन से संचालित होता है और लगातार 12 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम बताया गया है।

तेजस्वान में जीपीएस स्पूफिंग-रोधी नेविगेशन, मल्टी-बैंड रेडियो आधारित इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हार्डनिंग जैसी तकनीकें शामिल हैं। इसकी रेंज करीब 150 किलोमीटर है, जिसे जरूरत के अनुसार 250 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। इसका टेक-ऑफ वजन 60 किलोग्राम से कम है और यह 5 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है। इसकी अधिकतम गति 25 मीटर प्रति सेकंड बताई गई है और उड़ान भरने के लिए करीब 200 मीटर रनवे की आवश्यकता होती है। इस ड्रोन का इस्तेमाल निगरानी, संचार, लक्ष्य निर्धारण, समुद्री निगरानी और खोज एवं बचाव अभियानों में किया जा सकता है। रक्षा तकनीक के क्षेत्र में 'काल' ड्रोन भी विजिटर्स की जिज्ञासा का केंद्र बना है। यह वन-वे अटैक ड्रोन प्रणाली है, जो करीब 1000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है और 7 से 8 घंटे तक उड़ान में रह सकती है।

जिंदगी की जंग हार गई बोरवेल में गिरी तीन वर्षीय नेहा

फरीदाबाद। फरीदाबाद में गहरे बोरवेल में गिरी तीन साल की बच्ची नेहा को करीब 10 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सोमवार सुबह 4 बजे बाहर निकाला गया। बच्ची के शरीर में कोई हलचल नहीं थी। उसे तुरंत निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्ची के शव का पोस्टमॉर्टम कराया जाएगा। इससे उसकी मौत के सही कारणों का पता चलेगा। बच्ची को बाहर निकालने के लिए हरियाणा पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौके पर जुटी रहीं। एनडीआरएफ के अधिकारी ने बताया कि रविवार रात करीब 8 बजे उन्हें बच्ची के बोरवेल में गिरने की सूचना मिली थी।

टीम करीब 9 बजे गाजियाबाद से मौके पर पहुंच गई। उस समय अन्य विभागों की टीमें भी बचाव कार्य में जुटी थीं। नगर निगम की ओर से बोरवेल की गहराई करीब 300 फीट बताई गई थी। शुरुआत में बचाव दल को बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन कुछ देर बाद आवाज आनी बंद हो गई। टीम के साथ लाए गए उपकरण बोरवेल में काम नहीं कर पाए। इसके बाद स्थानीय कार पेंटर की मदद से मौके पर ही एक उपकरण तैयार किया गया। एसडीआरएफ अधिकारियों ने बताया कि बोरवेल कई साल से बंद था। लेकिन 125 फीट की गहराई पर बोरवेल में पानी भरा हुआ था। इससे रेस्क्यू आपरेशन में

भी काफी परेशानी आई। बच्ची का सिर नीचे की तरफ था। काफी मशक्कत के बाद टीम ने उसके पैर की मदद से उसे बाहर निकाला। बच्ची करीब 200 फीट से ज्यादा गहराई पर अटकी हुई थी। रविवार शाम तीन साल की नेहा बस्ती के बच्चों के साथ बोरवेल के पास खेल रही थी। इसी दौरान वह खुले बोरवेल में गिर गई। बच्ची के गिरते ही साथ खेल रहे बच्चों ने शोर मचा दिया।

आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उसके पिता रामदीन को सूचना दी। नेहा के पिता रामदीन मजदूरी करते हैं। हादसे के समय वह काम से वापस लौट रहे थे। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के रहने वाले रामदीन कई साल से सीही गांव में परिवार के साथ रह रहे हैं और यहीं मजदूरी करते हैं। निगम के कार्यकारी अभियंता संजीव कुमार ने बताया कि करीब 15 साल पहले बोरवेल को ढक्कन लगाकर बंद किया गया था। ढक्कन हटने की जानकारी निगम को नहीं मिली थी। उन्होंने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी। जांच में जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बच्ची की मौत के बाद सेक्टर-8 के लोगों में निगम के प्रति गुस्सा है। लोगों का आरोप है कि बोरवेल को अगर पूरी तरह सुरक्षित तरीके से बंद किया गया होता, तो यह हादसा नहीं होता।

एसआईआर पर राहुल गांधी का नैरेटिव बेनकाब : डॉ. अर्चना गुप्ता

पलवल। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने एसआईआर को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी रोज नए आरोप और नया नैरेटिव लेकर संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक अंग्रेजी समाचार पत्र की रिपोर्ट के आधार पर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए गए, जबकि मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों के संयुक्त प्रेस नोट में स्पष्ट किया गया कि एसआईआर की प्रक्रिया तीनों की सहमति से हुई है और किसी प्रकार की असहमति नहीं थी। सोमवार को लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह में पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉ. अर्चना गुप्ता ने कहा कि राहुल गांधी देश के गरिमापूर्ण पद पर हैं। ऐसे में संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करना उचित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस आमजन को गुमराह करने के लिए भ्रामक नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि एसआईआर का उद्देश्य पात्र मतदाताओं को सुनिश्चित करना और मतदाता सूची का शुद्धीकरण करना है।

लोन दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी, दो खाताधारक गिरफ्तार

फरीदाबाद। लोन दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने के मामले में साइबर थाना एनआईटी पुलिस ने दो खाताधारकों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपित जुड़वा भाई है। दोनों आरोपितों को सोमवार अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पुलिस प्रवक्ता अनुसार पर्वतीय कॉलोनी फरीदाबाद निवासी एक व्यक्ति ने साइबर थाना एनआईटी में दी अपनी शिकायत में बताया कि मई 2026 में उसके पास एक अंजान नंबर से कॉल आया जिसने उसे लोन दिलाने का ऑफर दिया और कहा कि उसे इस लोन के अलावा कोई भी शुल्क नही देना पडेगा परंतु कथित व्यक्ति ने शिकायतकर्ता को लोन 15.8 प्रतिशत की दर पर दिलाया और 22,000 रुपये का एक अन्य शुल्क भी लगा दिया। इस तरह इस ब्याज की दर व 22,000 रुपये रिफंड दिलाने के नाम पर कथित व्यक्ति ने शिकायतकर्ता से 2,00,000 रुपये ट्रांसफर करवा लिये। जिसके बाद उसे कोई पैसा वापस नही मिला, जिस शिकायत पर साइबर थाना एनआईटी में संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच आरंभ की गई। उन्होंने बताया कि साइबर थाना एनआईटी की टीम ने कार्रवाई करते हुए दो खाताधारकों को साकेत मेट्रो स्टेशन दिल्ली से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है जिनके नाम शुभ व शुभांश वासी महरौली दिल्ली है।

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि दोनों आरोपित जुड़वा भाई है। शुभ के खाता में ठगी के 1,80,000 रुपये व शुभांश के खाता में 20,000 रुपये आये थे। शुभ बीटेक व शुभांश बीबीए की पढाई कर रहा है। एक अन्य मामले में रीसाइक्लिंग प्रोजेक्ट में निवेश करने के नाम पर एक लाख रुपये की ठगी करने के मामले में पुलिस ने खाताधारक को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपित की पहचान ऋषभ सिकरवार निवासी धौलपुर राजस्थान को आगरा उत्तर प्रदेश के रुप में हुई है।

प्रभावी पुलिसिंग में मीडिया, आमजन का सहयोग महत्वपूर्णः डीजीपी अजय सिंघल

गुरुग्राम। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अजय सिंघल ने सोमवार को यहां सेक्टर-17/18 में नवनिर्मित पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया। साथ ही पुलिसकर्मियों, उनके परिवारों, वरिष्ठ अधिकारियों, मीडिया और शहर के प्रबुद्ध नागरिकों से संवाद किया।

गुरुग्राम पहुंचने पर पुलिस स्टेशन सेक्टर-17/18 में डीजीपी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद उन्होंने नई थाना बिल्डिंग का विधिवत उद्घाटन किया और परिसर का निरीक्षण कर पुलिसिंग से जुड़ी सुविधाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर पुलिस आयुक्त गुरुग्राम शिबास कबिराज सहित सभी पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद डीजीपी अजय सिंघल ने मीडिया से बात करते हुए गुरुग्राम की कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और पुलिस की कार्यशैली पर जानकारी सांझा की। उन्होंने कहा कि प्रभावी पुलिसिंग में मीडिया और आमजन का सहयोग बेहद महत्वपूर्ण है। पुलिस और जनता के बीच बेहतर तालमेल से ही सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। इसके बाद डीजीपी पुलिस लाइन पहुंचे। वहां उन्होंने कम्युनिटी हॉल में वेलफेयर मीटिंग की। उन्होंने पुलिसकर्मियों से सीधे संवाद कर उनकी कार्य परिस्थितियों, सुविधाओं और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। एचपीएससी गेस्ट हाउस में डीजीपी ने पुलिसकर्मियों के परिवारों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि पुलिस बल के साथ-साथ उनके परिवारों का कल्याण भी प्राथमिकता है। पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में लॉ एंड ऑर्डर कंपनियों ने विशेष डेमो प्रस्तुत किया। ईस्ट, वेस्ट, साउथ, मानेसर, मुख्यालय और महिला लॉ एंड ऑर्डर कंपनी के जवानों ने विभिन्न परिस्थितियों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने की तैयारियों का प्रदर्शन किया। पुलिस महानिदेशक ने कंपनियों के अनुशासन, तैयारी और समन्वय का निरीक्षण किया। दौरे के दौरान उन्होंने कमिश्नरेट कार्यालय में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में गुरुग्राम की मौजूदा पुलिसिंग व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, शिकायतों के त्वरित और संवेदनशील निवारण पर विस्तार से चर्चा हुई।

मंदिर के पुजारी की हत्या करने वाले दो आरोपित गिरफ्तार

फरीदाबाद। सेक्टर-30 बाईपास रोड पर नहर किनारे मंदिर के पास पुजारी की हत्या के मामले का अपराध शाखा डीएलएफ की टीम ने खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि मंदिर के पास नशा करने से रोकने को लेकर आरोपितों ने पुजारी के साथ मारपीट की। इसी दौरान पत्थर के सिल-बट्टा से सिर में चोट मारकर पुजारी को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे पुजारी की मृत्यु हो गई। इसके बाद आरोपित मंदिर से पुजारी का सामान लेकर मौके से फरार हो गए।

एसीपी क्राइम अमन यादव ने सोमवार को प्रेस कांफ्रेंस के दौरान बताया कि 30/31 अगस्त की रात सेक्टर-30 बाईपास रोड पर नहर के साथ सुनसान जगह पर बने मंदिर के पास पुजारी ओमप्रकाश (65) की सिर में चोट मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के चाचा के लडक़े अशोक कुमार, निवासी अहीरवाड़ा ओल्ड फरीदाबाद, की शिकायत पर थाना सेक्टर-31 में हत्या की धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया, अपराध शाखा डीएलएफ की टीम द्वारा मामले की जांच की जा रही थी। उन्होंने आगे बताया कि दोनों आरोपी आपस में दोस्त हैं, एक ही कॉलोनी में रहते हैं और नशा करने

के आदी हैं। पूछताछ में सामने आया कि 30 अगस्त की रात को वे अपने दो अन्य साथियों के साथ सेक्टर-30 बाईपास रोड कट के पास नहर किनारे मंदिर के पास नशा कर रहे थे। इसी दौरान पुजारी वहां पहुंचा और उन्हें नशा करने से मना करते हुए वहां से जाने को कहा गया। इसी को लेकर आरोपियों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया। चारों आरोपी पुजारी के पीछे मंदिर के पास पहुंचे, उसके साथ मारपीट की और पत्थर के सिल-बट्टा से पुजारी के सिर में चोट मारी, जिससे पुजारी की मृत्यु हो गई। वारदात के बाद आरोपी पुजारी का सामान लेकर मौके से फरार हो गए। उन्होंने आगे बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आशिफ (20), निवासी गांव हुसैनी, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश, हाल किसान मजदूर कॉलोनी, बाईपास रोड, फरीदाबाद तथा आशिफ (34), निवासी गांव बामनी, थाना जुरहेड़ा, जिला भरतपुर, राजस्थान, हाल किसान मजदूर कॉलोनी, बाईपास रोड, फरीदाबाद के रूप में हुई है। दोनों आरोपी ऑटो चलाने का काम करते हैं। नशा करने की आदी हैं।

लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए गंभीर चिंता का विषय

सौरभ वार्ष्णेय

चुनाव आयोग के फैसलों पर 14 बार लिखित आपत्ति की अनदेखी का मतलब है कि केंद्रीय चुनाव आयोग में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। लोकतंत्र केवल चुनाव कराने की प्रक्रिया का नाम नहीं है। लोकतंत्र की वास्तविक मजबूती इस बात से तय होती है कि चुनाव कितने पारदर्शी, निष्पक्ष और विश्वसनीय तरीके से कराए जाते हैं। ऐसे में चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था के भीतर उठने वाली किसी भी असहमति को महज प्रशासनिक प्रक्रिया मानकर नजरअंदाज करना उचित नहीं होगा। मतदाता सूची से जुड़े फैसलों पर चुनाव आयोग के दो आयुक्तों की ओर से बार-बार यानी 14 बार लिखित आपत्ति दर्ज किए जाने की खबर ने इसी कारण गंभीर सवाल खड़े किए हैं। राजनीतिज्ञों को भी सोचने को मजबूर कर दिया है कि इसका हल कैसे निकाले ? वहीं ऐसी बातों से मतदाताओं के बीच भी लोकतंत्र की इस संवैधानिक संस्था के प्रति सोचना पड़ता है। यह ऐसे संस्था है कि जहां कुछ भी हो तुरंत प्रभावी कार्य हो जिससे पारदर्शिता सबके सामने आये।

देश के प्रतिष्ठित अखबार में प्रकाशित एक रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद देश में राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले करीब दस महीनों में आयोग के विभिन्न फैसलों और आदेशों पर कम से कम 14 बार लिखित आपत्तियां दर्ज कराईं। बताया गया है कि इन आपत्तियों का संबंध केवल तकनीकी या प्रक्रियागत विषयों तक सीमित नहीं था, बल्कि मतदाता सूची में नाम जोडने और हटाने, फॉर्म-6 में बदलाव, मतदाता डेटा के केंद्रीकरण तथा चुनावी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली तक अधिकारियों की पहुंच जैसे संवेदनशील मुद्दों से था। यहां मूल चिंता यह नहीं है कि किसी संवैधानिक संस्था में अलग-अलग राय क्यों सामने आईं। लोकतांत्रिक संस्थाओं में असहमति अपने आप में कोई कमजोरी नहीं है। बल्कि स्वस्थ संस्थागत व्यवस्था में अलग राय रखना और उसे रिकॉर्ड पर दर्ज करना एक आवश्यक प्रक्रिया मानी जाती है। चिंता तब पैदा होती है जब यह सवाल उठे कि क्या उन आपत्तियों पर पर्याप्त विचार किया गया और क्या निर्णय प्रक्रिया वास्तव में सभी संबंधित सदस्यों की भागीदारी से आगे बढ़ी? चुनाव आयोग तीन सदस्यीय संवैधानिक संस्था है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी इसके सदस्य हैं। यदि दो सदस्यों की ओर से महत्वपूर्ण मामलों में बार-बार लिखित आपत्तियां दर्ज की गई हैं, तो इन आपत्तियों की प्रकृति, उनका निस्तारण और अंतिम निर्णय तक पहुंचने की प्रक्रिया सार्वजनिक विमर्श का विषय बनना स्वाभाविक है। विशेष रूप से मतदाता सूची का मामला अत्यंत संवेदनशील है। मतदाता सूची केवल प्रशासनिक दस्तावेज नहीं होती। यही वह आधार है जो तय करती है कि चुनाव के दिन कौन नागरिक अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेगा। इसलिए मतदाता सूची में किसी नाम का जुडना, हटना या बहाल होना सीधे तौर पर नागरिक के लोकतांत्रिक अधिकार से जुड़ा प्रश्न है। फॉर्म-6 में बदलाव को लेकर सामने आई आपत्ति इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण है। फॉर्म-6 नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला वैधानिक फॉर्म है। रिपोर्ट के अनुसार, विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान इसमें ऐसा घोषणा-पत्र जोड़ा गया, जिसमें आवेदक से यह बताने को कहा गया कि उसका या उसके माता-पिता अथवा दादा-दादी का नाम पिछली मतदाता सूची में था या नहीं। यदि किसी प्रक्रिया में इस तरह का महत्वपूर्ण बदलाव किया जा रहा हो और उससे पहले आयोग के ही दो सदस्यों की आपत्ति सामने आई हो, तो यह जानना जरूरी हो जाता है कि उस आपत्ति पर क्या विचार हुआ और बदलाव का अंतिम आधार क्या था।

मामला केवल कागजी प्रक्रिया तक सीमित नहीं है। मतदाता सूची के डिजिटल प्रबंधन को लेकर भी सवाल उठे हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कुछ राज्यों में स्थानीय स्तर के निर्वाचन अधिकारियों की मतदाता डेटा से जुड़े फैसलों को सिस्टम में दर्ज करने की क्षमता प्रभावित हुई। पश्चिम बंगाल में कुछ ऐसे मामलों का भी उल्लेख है, जहां दस्तावेजों की जांच के बाद लोग पात्र पाए गए, लेकिन सॉफ्टवेयर में उनके नाम जोडने की प्रक्रिया को लेकर तकनीकी बाधाएं सामने आईं। गोवा में 97 पात्र मतदाताओं का मामला भी इसी तरह की तकनीकी समस्या से जुड़ा बताया गया है। यह स्थिति एक बुनियादी सवाल खड़ा करती है कि चुनावी प्रक्रिया में अंतिम निर्णय किसका होगा, मैदानी स्तर पर काम कर रहा निर्वाचन अधिकारी या केंद्रीकृत डिजिटल सिस्टम ? तकनीक चुनावी प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने का माध्यम हो सकती है, लेकिन वह लोकतांत्रिक निर्णय का विकल्प नहीं बन सकती। किसी तकनीकी प्रणाली में हुई त्रुटि के कारण यदि पात्र मतदाता का नाम सूची में शामिल नहीं हो पाता, तो इसका सीधा असर उसके मताधिकार पर पड़ सकता है। हालांकि, इस पूरे विवाद का दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। चुनाव आयोग ने रिपोर्ट में बताए गए कथित आंतरिक मतभेद के निष्कर्ष को खारिज किया है। आयोग का कहना है कि सदस्यों की ओर से नोटिंग, टिप्पणियां, सुझाव और अलग-अलग राय देना सामान्य संस्थागत प्रक्रिया का हिस्सा है। आयोग के अनुसार, अनुच्छेद 324, वैधानिक नियमों और स्थापित प्रक्रियाओं के तहत विचार-विमर्श के बाद अंतिम फैसले लिए जाते हैं और एसआईआर सहित महत्वपूर्ण निर्णय तीनों आयुक्तों की मंजूरी से हुए हैं। इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि लिखित आपत्तियां अपने आप में आयोग के भीतर किसी निर्णायक विभाजन का प्रमाण हैं। लेकिन यह भी उतना ही सही है कि ऐसी आपत्तियों को पूरी तरह सामान्य प्रशासनिक टिप्पणी कहकर सार्वजनिक चिंता को समाप्त नहीं किया जा सकता। यदि 14 बार लिखित आपत्तियां दर्ज हुई हैं, तो लोकतांत्रिक पारदर्शिता की मांग यही होगी कि कम से कम यह स्पष्ट किया जाए कि किन मुद्दों पर असहमति थी, उन पर क्या विचार हुआ और अंतिम निर्णय किस प्रक्रिया के तहत लिया गया।

विपक्ष ने इन घटनाओं को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग की है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट से स्वत: संज्ञान लेने की मांग की है, जबकि राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई और विशेष गहन पुनरीक्षण रोकने की मांग उठाई है। राहुल गांधी ने भी मतदाता सूची से जुड़े मुद्दे को लोकतांत्रिक अधिकारों और संविधान से जोड़ा है। इन राजनीतिक दावों की अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि है, इसलिए इनका मूल्यांकन स्वतंत्र तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर ही किया जाना चाहिए। असल चुनौती किसी एक व्यक्ति या राजनीतिक दल की नहीं, बल्कि चुनावी संस्थाओं पर जनता के भरोसे की है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता लोकतंत्र की बुनियादी पूंजी है। इसलिए आयोग के भीतर असहमति सामने आए तो उसका समाधान अधिक पारदर्शिता, स्पष्ट जवाबदेही और सार्वजनिक स्पष्टीकरण से होना चाहिए, न कि केवल विवाद को खारिज कर देने से। जरूरत इस बात की है कि मतदाता सूची से जुड़े सभी महत्वपूर्ण बदलावों का स्पष्ट ऑडिट ट्रेल उपलब्ध हो। किस अधिकारी ने क्या निर्णय लिया, किस आधार पर लिया, किस स्तर पर उसे बदला गया और तकनीकी प्रणाली ने उस निर्णय को कैसे दर्ज किया। इन सवालों के जवाब लोकतांत्रिक व्यवस्था में अस्पष्ट नहीं रहने चाहिए। साथ ही, आयोग के भीतर दर्ज असहमति और उसके निस्तारण की संस्थागत प्रक्रिया भी स्पष्ट होनी चाहिए। चुनाव लोकतंत्र का उत्सव तभी बन सकता है, जब हर पात्र नागरिक को यह भरोसा हो कि उसका नाम मतदाता सूची में सुरक्षित है और चुनावी प्रक्रिया किसी अदृश्य तकनीकी या प्रशासनिक हस्तक्षेप से प्रभावित नहीं होगी। चुनाव आयोग के दो सदस्यों की 14 लिखित आपत्तियों का मामला इसी भरोसे की कसौटी है। असहमति लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं होती; असहमति को सुनने और उसका पारदर्शी समाधान न करने की व्यवस्था जरूर लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए गंभीर चिंता का विषय बन सकती है।

आईआईटी और अन्य केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी विद्यार्थियों से जुड़े भेदभाव, सामाजिक अलगाव, अकादमिक दबाव और ड्रॉपआउट की घटनाओं पर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं। सोशल मीडिया और सार्वजनिक बहस में छात्रों की आत्महत्याओं में किसी एक सामाजिक वर्ग की बहुत बड़ी हिस्सेदारी के दावे भी किए जाते हैं, लेकिन ऐसे दावों को प्रमाणित सरकारी डेटा, स्पष्ट समयावधि और विश्वसनीय अध्ययन के बिना अंतिम तथ्य मान लेना उचित नहीं है। फिर भी यदि किसी विद्यार्थी को उसकी जाति, वर्ग, भाषा, क्षेत्र, आर्थिक स्थिति या किसी अन्य सामाजिक पहचान के कारण अतिरिक्त मानसिक दबाव या भेदभाव झेलना पड़ता है, तो यह शिक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर चेतावनी है। प्रतिभा का मूल्यांकन विद्यार्थी की क्षमता से होना चाहिए, उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि से नहीं। साथ ही यह भी समझना होगा कि हर आत्महत्या का कारण केवल भेदभाव या संस्थागत उत्पीड़न नहीं होता। कई बार परीक्षा और प्रदर्शन का दबाव, असफलता का भय, परिवार की अपेक्षाएं, आर्थिक कठिनाइयां, अकेलापन, रिश्तों से जुड़ी समस्याएं, भविष्य की चिंता और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां एक साथ काम करती हैं।

कैंपस में बुझती जिंदगियाँ: आत्महत्या नहीं, व्यवस्था की भी परीक्षा

डॉ. प्रियंका सौरभ

आईआईटी बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोडे की मौत ने देश के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों की चमकदार इमारतों के पीछे छिपे एक गंभीर सवाल को फिर सामने ला खड़ा किया है—क्या हमारे उच्च शिक्षण संस्थान प्रतिभा को केवल परख रहे हैं, या उसे संभालने की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं? साहिल की मृत्यु की परिस्थितियों की जांच अभी जारी है। इसलिए इस समय किसी एक व्यक्ति, घटना या कथित भेदभाव को उनकी आत्महत्या का अंतिम कारण घोषित करना उचित नहीं होगा। उनके परिजनों ने जातिगत भेदभाव और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं, जबकि संस्थान की ओर से कहा गया है कि उसे ऐसी कोई औपचारिक शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी। ऐसे में सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता निष्पक्ष और पारदर्शी जांच से ही होकर गुजरना चाहिए। लेकिन जांच के निष्कर्ष का इंतजार करते हुए भी एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है—आखिर देश के प्रतिभाशाली युवा इतनी बड़ी संख्या में अपनी जिंदगी क्यों समाप्त कर रहे हैं? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े इस संकट की गंभीरता की ओर संकेत करते हैं। 2013 में देश में छात्रों द्वारा आत्महत्या के 8,423 मामले दर्ज हुए थे। 2023 में यह संख्या बढ़कर 13,892 और 2024 में 14,488 तक पहुंच गई। यानी एक दशक से अधिक समय में दर्ज मामलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हालांकि इन आंकड़ों को केवल संख्या के रूप में देखकर निष्कर्ष निकालना भी उचित नहीं होगा, क्योंकि इस अवधि में विद्यार्थियों की कुल आबादी और उच्च शिक्षा में नामांकन भी बढ़ा है। इसलिए छात्र आबादी के अनुपात में आत्महत्या की दर, आयु, लिंग, सामाजिक पृष्ठभूमि, संस्थान, पाठ्यक्रम और क्षेत्र के आधार पर विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है। फिर भी इतना स्पष्ट है कि छात्र आत्महत्या अब व्यक्तिगत घटनाओं की अलग-अलग खबर नहीं रह गई है, बल्कि यह राष्ट्रीय चिंता का विषय बन चुकी है।

आईआईटी जैसे संस्थानों में यह सवाल और गंभीर हो जाता है। शिक्षा मंत्रालय ने संसद में बताया था कि 2018 से 2023 के बीच आईआईटी परिसरों में 39 छात्रों की आत्महत्या से मृत्यु हुई। दूसरी ओर, अलग-अलग आरटीआई प्रतिक्रियाओं और मीडिया रिपोर्टों पर आधारित संकलनों में इससे अधिक संख्या सामने आती रही है। अलग-अलग स्रोतों में संख्या अलग होने का एक कारण यह भी है कि उनकी समयावधि, परिभाषा और डेटा-संग्रह की पद्धति समान नहीं है। इसलिए किसी एक आंकड़े को अंतिम सत्य मानने के बजाय सरकारी रिकॉर्ड, संस्थागत रिकॉर्ड और स्वतंत्र अध्ययनों को एक साथ रखकर राष्ट्रीय स्तर पर विश्वसनीय डेटाबेस तैयार किया जाना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होता, बहस आंकड़ों और दावों के बीच उलझती रहेगी और समस्या की वास्तविक तस्वीर सामने नहीं आ पाएगी। इस पूरी बहस में सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। आईआईटी और अन्य केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी विद्यार्थियों से जुड़े भेदभाव, सामाजिक अलगाव, अकादमिक दबाव और ड्रॉपआउट की घटनाओं पर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं। सोशल मीडिया और सार्वजनिक बहस में छात्रों की आत्महत्याओं में किसी एक सामाजिक वर्ग की बहुत बड़ी हिस्सेदारी के दावे भी किए जाते हैं, लेकिन ऐसे दावों को प्रमाणित सरकारी डेटा, स्पष्ट समयावधि और विश्वसनीय अध्ययन के बिना अंतिम तथ्य मान लेना उचित नहीं है। फिर भी यदि किसी विद्यार्थी को उसकी जाति, वर्ग, भाषा, क्षेत्र, आर्थिक स्थिति या किसी अन्य सामाजिक पहचान के कारण अतिरिक्त मानसिक दबाव या भेदभाव झेलना पड़ता है, तो यह शिक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर चेतावनी है। प्रतिभा का मूल्यांकन विद्यार्थी की क्षमता से होना चाहिए, उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि से नहीं। साथ ही यह भी समझना होगा कि हर आत्महत्या का कारण केवल भेदभाव या संस्थागत उत्पीड़न नहीं होता। कई बार परीक्षा और प्रदर्शन का दबाव, असफलता का भय, परिवार की अपेक्षाएं, आर्थिक कठिनाइयां, अकेलापन, रिश्तों से जुड़ी समस्याएं, भविष्य की चिंता और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां एक साथ काम करती हैं। कई मामलों में कारणों की पूरी श्रृंखला घटना के बाद भी स्पष्ट नहीं हो पाती। इसलिए किसी भी छात्र की मृत्यु को केवल एक कारण से जोड़ देना उतना ही खतरनाक है जितना संस्थागत समस्याओं की संभावना को पूरी तरह नकार देना। आवश्यकता इस बात की है कि हर घटना की स्वतंत्र, संवेदनशील और वैज्ञानिक तरीके से कारण-पड़ताल हो और उसके निष्कर्षों को संस्थागत सुधार से जोड़ा जाए। उच्च शिक्षण संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य को अब वैकल्पिक सुविधा नहीं, बल्कि मूलभूत संस्थागत जिम्मेदारी मानना होगा। केवल काउंसलिंग सेंटर का बोर्ड लगा देना पर्याप्त नहीं है। विद्यार्थियों के लिए आसानी से उपलब्ध और गोपनीय मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं, प्रशिक्षित काउंसलर, संवेदनशील वार्डन, प्रशिक्षित फैकल्टी मेंटर, भरोसेमंद शिकायत प्रणाली और समयबद्ध शिकायत-निवारण व्यवस्था जरूरी है। यदि किसी विद्यार्थी को जातिगत भेदभाव, रैगिंग, बुलिंग, लैंगिक उत्पीड़न, अकादमिक अपमान या किसी अन्य प्रकार के दबाव का सामना करना पड़ रहा है तो उसे यह भरोसा होना चाहिए कि उसकी शिकायत सुनी जाएगी और उसके खिलाफ प्रतिशोध नहीं होगा। इसी तरह संस्थानों को अनुशासन, परीक्षा की निष्पक्षता और अकादमिक मानकों को भी बनाए रखना होगा। संवेदनशीलता और गुणवत्ता एक-दूसरे की विरोधी नहीं, बल्कि एक-दूसरे की पूरक हो सकती हैं।

सबसे बड़ी आवश्यकता उस संस्कृति को बदलने की है जिसमें असफलता को अपराध और मदद मांगने को कमजोरी समझ लिया जाता है। आईआईटी में प्रवेश जीवन की अंतिम उपलब्धि नहीं है और किसी परीक्षा में असफल होना जीवन की असफलता नहीं हो सकता। एक विषय में कम अंक, किसी परीक्षा में असफलता, पाठ्यक्रम बदलने की इच्छा या करियर को लेकर असमंजस जीवन के स्वाभाविक पड़ाव हो सकते हैं। लेकिन जब विद्यार्थी को लगता है कि उसके पास लौटने, रुकने या सहायता मांगने का कोई रास्ता नहीं है, तब संकट गहरा सकता है। इसलिए परिवार, शिक्षक और संस्थान तीनों को यह समझना होगा कि विद्यार्थी केवल अंक, रैंक या प्लेसमेंट का आंकड़ा नहीं है; वह भावनाओं, आकांक्षाओं और संघर्षों वाला एक मनुष्य है। हमने शिक्षा को सफलता की सीढ़ी तो बना दिया, लेकिन उसे जीवन जीने की तैयारी बनाने पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया। माता-पिता बच्चे से सफलता चाहते हैं, संस्थान उत्कृष्टता चाहते हैं और समाज रैंक चाहता है; लेकिन विद्यार्थी किस मानसिक दबाव से गुजर रहा है, उसे किस बात का डर है और वह किससे अपनी परेशानी साझा कर सकता है—इन सवालों के लिए अक्सर पर्याप्त समय नहीं निकलता। यही वह जगह है जहां शिक्षा व्यवस्था को आत्ममंथन करना होगा। साहिल की मौत की जांच अपना रास्ता तय करेगी। उनके परिवार द्वारा लगाए गए आरोप सही हैं या नहीं, यह निष्पक्ष जांच और उपलब्ध साक्ष्यों से तय होना चाहिए। लेकिन इस घटना से उठे सवालों को केवल एक छात्र, एक संस्थान या एक घटना तक सीमित कर देना भी उचित नहीं होगा। देश को यह तय करना होगा कि उसके शीर्ष शिक्षण संस्थान केवल श्रेष्ठ इंजीनियर, वैज्ञानिक, डॉक्टर और शोधकर्ता तैयार करेंगे या ऐसे संवेदनशील मनुष्य भी तैयार करेंगे जिन्हें कठिन समय में संभाला जा सके। एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी की मृत्यु केवल उसके परिवार की त्रासदी नहीं होती; वह पूरी शिक्षा व्यवस्था के सामने खड़ा एक कठोर प्रश्न होती है। इस प्रश्न का उत्तर आरोप-प्रत्यारोप, सोशल मीडिया की बहस या आंकड़ों की राजनीति से नहीं, बल्कि पारदर्शी जांच, विश्वसनीय आंकड़ों, वैज्ञानिक अध्ययन, संवेदनशील संस्थागत सुधार और हर विद्यार्थी के जीवन को सर्वोच्च महत्व देने वाली संस्कृति से देना होगा। आखिर किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी उसकी इमारतें, संस्थान या रैंकिंग नहीं, बल्कि उसके युवा हैं। यदि वही युवा असहाय होकर जीवन से हारने लगें, तो हमें केवल यह नहीं पूछना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया; हमें यह भी पूछना चाहिए कि उनके आसपास की व्यवस्था उन्हें बचाने के लिए समय पर क्या कर रही थी।

विचार

बच्चों के हाथ में मोबाइल बढ़ा तो बचपन हुआ डिजिटल कैद

कांतिलाल मांडोत

आज के समय में मोबाइल फोन जीवन की आवश्यकता बन चुका है। पढ़ाई, जानकारी, संवाद और मनोरंजन से लेकर अनेक जरूरी काम स्मार्टफोन के माध्यम से पूरे किए जा रहे हैं। लेकिन जब यही सुविधा बच्चों की आदत और फिर लत में बदलने लगे तो यह चिंता का विषय बन जाता है। देश में बच्चों और किशोरों के बीच स्मार्टफोन का इस्तेमाल जिस तेजी से बढ़ रहा है, उसने अभिभावकों और समाज के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। खासकर 10 से 19 वर्ष की उम्र के बच्चे डिजिटल दुनिया में तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2020 में 15 से 19 वर्ष के करीब 49 प्रतिशत बच्चे स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे थे, जो 2023 तक बढ़कर 91 प्रतिशत से अधिक हो गया। यानी तीन वर्ष में उपयोग में लगभग 42 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। बच्चों में स्मार्टफोन की पहुंच केवल किशोरों तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार 8 से 18 वर्ष की उम्र के करीब 30 प्रतिशत बच्चों के पास अपना व्यक्तिगत फोन है, जबकि 62 प्रतिशत बच्चे माता-पिता के फोन का इस्तेमाल करते हैं। वर्ष 2026 की शुरुआत तक 10 से 14 वर्ष की उम्र के लगभग 83 प्रतिशत बच्चों की स्मार्टफोन तक पहुंच बताई गई है। यह आंकड़ा वैश्विक औसत से भी अधिक है। ऐसे में यह समझना जरूरी हो जाता है कि मोबाइल केवल बच्चों के हाथ में पहुंचने वाली तकनीक नहीं है, बल्कि उसका इस्तेमाल उनके व्यवहार, सोच, पढ़ाई, सामाजिक संबंध और सुरक्षा को भी प्रभावित कर सकता है।

बच्चों को मोबाइल देने की शुरुआत अक्सर बहुत सामान्य कारणों से होती है। बच्चा खाना नहीं खा रहा हो, जिद कर रहा हो, रो रहा हो या शरारत कर रहा हो तो उसे शांत करने के लिए मोबाइल हाथ में थमा दिया जाता है। धीरे-धीरे बच्चा मोबाइल को मनोरंजन का सबसे आसान साधन मानने लगता है। माता-पिता भी व्यस्तता के कारण कई बार इस आदत पर तत्काल ध्यान नहीं देते। बच्चे की जिद पूरी करना उस समय आसान समाधान दिखाई देता है, लेकिन यही सुविधा आगे चलकर आदत का रूप ले सकती है। जब बच्चा हर खाली समय मोबाइल पर बिताने लगे और मोबाइल न मिलने पर बेचैनी दिखाए तो अभिभावकों को इसे गंभीर संकेत मानना चाहिए। मोबाइल और इंटरनेट का सही इस्तेमाल बच्चों के लिए ज्ञान और सीखने का माध्यम बन सकता है। समस्या तब पैदा होती है जब स्क्रीन का उपयोग जरूरत से अधिक होने लगे। कई बच्चे प्रतिदिन सात से दस घंटे तक स्क्रीन के सामने समय बिताने लगे हैं। इससे पढ़ाई के लिए मिलने वाला समय प्रभावित होता है और खेलकूद, परिवार के साथ बातचीत तथा सामाजिक गतिविधियों के लिए समय कम हो जाता है। लगातार स्क्रीन पर रहने की आदत बच्चों को वास्तविक दुनिया से दूर कर सकती है। मोबाइल पर मिलने वाला लगातार मनोरंजन उन्हें सामान्य गतिविधियों में कम रुचि लेने के लिए भी प्रेरित कर सकता है। बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा का पहलू इससे भी अधिक गंभीर है। इंटरनेट की दुनिया में अच्छी सामग्री के साथ ऐसी सामग्री भी मौजूद है जो बच्चों के लिए अनुपयुक्त और नुकसानदेह हो सकती है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार बच्चों के खिलाफ होने वाले 60 प्रतिशत से अधिक साइबर अपराध अश्लील सामग्री से जुड़े बताए गए हैं। यह स्थिति बताती है कि बच्चों को केवल स्मार्टफोन देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें इंटरनेट के सुरक्षित इस्तेमाल की जानकारी देना भी जरूरी है। अनजान लोगों से बातचीत, संदिग्ध संदेशों पर प्रतिक्रिया, निजी जानकारी साझा करना और अनुचित सामग्री के संपर्क में आना बच्चों को साइबर अपराधियों के निशाने पर ला सकता है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि अनेक बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षा के साधनों की पूरी जानकारी नहीं है। एक सर्वे में केवल 37.1 प्रतिशत युवाओं ने कहा कि वे सामग्री की शिकायत करने और सुरक्षा संबंधी उपकरणों का सही इस्तेमाल करना जानते हैं। वहीं पांच में से एक युवा को ऐसे सुरक्षा उपकरणों की जानकारी ही नहीं थी। ग्रामीण क्षेत्रों तथा 11 से 13 वर्ष की उम्र के बच्चों में जागरूकता का स्तर और कम पाया गया। इसका अर्थ साफ है कि इंटरनेट की पहुंच तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उसके सुरक्षित इस्तेमाल की समझ उसी गति से नहीं बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में अभिभावकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। बच्चों को मोबाइल से पूरी तरह दूर रखना हमेशा व्यावहारिक नहीं हो सकता, क्योंकि शिक्षा और ज्ञान के लिए भी डिजिटल माध्यम जरूरी हो चुके हैं। इसलिए प्रतिबंध के बजाय संतुलित उपयोग की आदत विकसित करना अधिक जरूरी है। माता-पिता को बच्चों के लिए मोबाइल इस्तेमाल का निश्चित समय तय करना चाहिए। पढ़ाई, भोजन, परिवार के साथ समय और सोने से पहले मोबाइल से दूरी जैसी आदतों को धीरे-धीरे दिनचर्या का हिस्सा बनाया जा सकता है। बच्चों को मोबाइल देने के बजाय उनके साथ समय बिताना भी जरूरी है। बच्चा जब जिद करे या परेशान हो तो हर बार मोबाइल को समाधान बनाने के बजाय उससे बातचीत करनी चाहिए।

एक नजर

जिला जज एवं सचिव ने छपरा मंडल कारा में क्षमता से अधिक बंदियों पर दिए कड़े निर्देश

सारण। जिला विधिक सेवा प्राधिकार सारण के अध्यक्ष-सह-जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनंत कुमार सिंह तथा डालसा सचिव राजीव कुमार ने आज मंडल कारा छपरा का विस्तृत निरीक्षण किया। कारागार पहुँचने पर जेल अधीक्षक अमरजीत सिंह ने पौधा भेंट कर जिला जज का स्वागत किया। इसके बाद अधिकारियों ने कारा परिसर में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने जेल परिसर की साफ-सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, बंदियों के खान-पान, स्वास्थ्य सेवाओं और उन्हें मिलने वाली विधिक सहायता की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, मंडल कारा की कुल क्षमता 1063 है, जिनमें 1001 पुरुष, 62 महिला बंदियों की है, जबकि वर्तमान में कुल 1703 बंदी जिनमें 1634 पुरुष, 69 महिला संसीमित हैं। इनमें 1576 विचाराधीन जिसमें 364 उत्पाद अधिनियम के तहत और 126 सजावार बंदी शामिल हैं। इसके अलावा 4 बंदी इलाज हेतु बाहर हैं तथा महिला बंदियों के साथ 7 बच्चे 5 बालक 2 बालिका भी रह रहे हैं। क्षमता से अधिक बंदियों की संख्या को देखते हुए जिला जज ने कारा प्रशासन को स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने जेल अस्पताल में संक्रामक बीमारियों से पीड़ित बंदियों के लिए पृथक एवं विशेष व्यवस्था करने को कहा। साथ ही, जिन बंदियों के पास पैरवी हेतु अधिवक्ता नहीं हैं, उन्हें प्राधिकार के माध्यम से त्वरित नि:शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के सख्त निर्देश दिए।

गंडक के बढ़ते जलस्तर पर सारण जिला प्रशासन अलर्ट

सारण। नेपाल में हो रही बारिश के कारण गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग द्वारा जारी वर्षा और आंधी के पूर्वानुमान को देखते हुए जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने प्रशासनिक तैयारियों की गहन समीक्षा की। गंडक नदी में अब तक लगभग 3 लाख क्यूसेक पानी पहुंच चुका है, जबकि 1.5 लाख क्यूसेक अतिरिक्त पानी आने की संभावना है।

स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को अगले दो-तीन दिनों तक हाई अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठक के दौरान गंडक नदी से प्रभावित होने वाले जिले के 7 तटवर्ती प्रखंडों में जलस्तर, तटबंधों की मजबूती और संभावित बाढ़ प्रभावित आबादी के लिए की गई पूर्व तैयारियों का जायजा लिया गया। जिलाधिकारी ने तटबंधों की सतत निगरानी और पेट्रोलिंग सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए हैं, ताकि रात के समय भी जलस्तर बढ़ने पर स्थिति पर काबू पाया जा सके। जलस्तर बढ़ने की सूरत में नदी और तटबंध के बीच बसे लोगों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने, राहत शिविरों और सामुदायिक रसोई की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। दरियापुर प्रखंड में लगभग 100 घरों के करीब 500 लोगों के प्रभावित होने की आशंका के आधार पर खाद्यान्न का अतिरिक्त स्टॉक कर लिया गया है। त्वरित राहत कार्य के लिए वेंडर्स को शॉर्ट नोटिस पर सामग्री उपलब्ध कराने हेतु चिन्हित किया गया है। स्थानीय विकास मित्रों, मुखियाओं और जनप्रतिनिधियों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर निगरानी की जा रही है। इसके अतिरिक्त, वर्षा और तेज आंधी की चेतावनी को देखते हुए सभी अंचल अधिकारियों द्वारा क्षेत्रों में माइकिंग करवाकर आमजन को जागरूक किया जा रहा है। लोगों से आंधी-पानी के दौरान घरों में ही रहने और सुरक्षित स्थानों पर आश्रय लेने की अपील की गई है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस पूर्व तैयारियों के साथ सतर्कता बरतने की जरूरत है।

अभियान बसेरा के तहत 3 डिसमिल जमीन के लिए आवेदन का अंतिम दिन, पिपरा अंचल में उमड़ी भीड़

सुपौल। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अभियान बसेरा 2.0 के तहत भूमिहीन परिवारों को वास भूमि उपलब्ध कराने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतिम दिन सोमवार को पिपरा प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में आवेदकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। 3 डिसमिल जमीन के लिए आवेदन जमा करने को लेकर सुबह से ही कार्यालय परिसर में महिला और पुरुष आवेदकों की लंबी कतारें लगी रहीं। सुबह करीब 10 बजे से ही बड़ी संख्या में लोग अपने हाथों में आधार कार्ड, आवास प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज और आवेदन पत्र लेकर प्रखंड कार्यालय पहुंचने लगे। देखते ही देखते कार्यालय परिसर में आवेदकों की भीड़ बढ़ गई। अंतिम दिन आवेदन जमा करने की जल्दबाजी के कारण दूर-दराज के गांवों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। कई आवेदकों ने बताया कि वे पिछले दो-तीन दिनों से आवेदन जमा करने के लिए कार्यालय का चक्कर लगा रहे थे, लेकिन किसी कारण से आवेदन जमा नहीं हो सका। सोमवार को अंतिम दिन होने की जानकारी के बाद वे सुबह ही कार्यालय पहुंच गए। पिपरा सीओ आकांक्षा ने बताया कि अभियान बसेरा 2.0 के तहत भूमिहीन परिवारों से आवेदन लेने के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। 22 से 25 सितंबर तक संबंधित पंचायत सरकार भवनों में विशेष कैंप लगाकर आवेदन लिए गए, जबकि 22 से 28 सितंबर तक अंचल कार्यालय में आवेदन जमा करने की व्यवस्था की गई। उन्होंने बताया कि आवेदन जमा करने वाले प्रत्येक आवेदक को पावती रसीद उपलब्ध कराई जा रही है। इससे आवेदन जमा होने की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी और आवेदक के पास भी आवेदन जमा करने का प्रमाण रहेगा। सीओ ने स्पष्ट किया कि 28 सितंबर को विशेष कैंप का अंतिम दिन है, लेकिन जो पात्र परिवार किसी कारणवश विशेष अभियान के दौरान आवेदन जमा नहीं कर पाते हैं, वे सामान्य दिनों में भी अंचल कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करना होगा। प्राप्त आवेदनों की जांच के बाद पात्र परिवारों का सत्यापन किया जाएगा। जांच में पात्र पाए जाने वाले भूमिहीन परिवारों को नियमानुसार वास भूमि का पर्चा उपलब्ध कराया जाएगा।

बिहार में धान खरीद का लक्ष्य 35 लाख से बढ़ाकर 50 लाख मीट्रिक टन करने की मांग : अशोक चौधरी

पटना,एजेंसी। बिहार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी ने खरीफ विपणन मौसम 2026-27 के लिए बिहार में निर्धारित धान खरीद के लक्ष्य को 35 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 50 लाख मीट्रिक टन करने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी को पत्र भेजकर आवश्यक स्वीकृति शीघ्र प्रदान करने का अनुरोध किया है। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि भारत सरकार ने पत्र के माध्यम से बिहार के लिए खरीफ विपणन मौसम 2026-27 हेतु धान खरीद का लक्ष्य 35.00 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है। धान खरीद की अवधि 01 नवंबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक निर्धारित है। पिछले वर्षों के आंकड़ों से स्पष्ट है कि बिहार में धान का अनुमानित उत्पादन लगातार बढ़ा है, जबकि कुल अनुमानित उत्पादन के अनुपात में धान खरीद का लक्ष्य लगातार कम होता गया है।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2023-24 में अनुमानित धान उत्पादन 133.26 लाख मीट्रिक टन था और खरीद लक्ष्य 45 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया था। वर्ष 2024-25 में अनुमानित उत्पादन बढ़कर 141.08 लाख मीट्रिक टन हुआ, जबकि खरीद लक्ष्य 45 लाख मीट्रिक टन रहा। वर्ष 2025-26 में अनुमानित उत्पादन 151.36 लाख मीट्रिक टन पहुंच गया, लेकिन खरीद लक्ष्य घटकर 36.85 लाख मीट्रिक टन रह गया। वहीं, वर्ष 2026-27 में अनुमानित धान उत्पादन 154.39 लाख मीट्रिक टन है, जबकि खरीद लक्ष्य मात्र 35 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है। चौधरी ने कहा कि 01 सितंबर 2026 को खाद्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्यों के खरीद लक्ष्य निर्धारण को लेकर चर्चा हुई थी। वर्तमान व्यवस्था में पिछले तीन वर्षों की औसत खरीद उपलब्धि के आधार पर लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। बिहार के संदर्भ में यह पद्धति राज्य में लगातार बढ़ रहे धान उत्पादन और किसानों की वास्तविक क्षमता के अनुरूप पर्याप्त खरीद लक्ष्य निर्धारित करने में बाधक है। उन्होंने आग्रह किया कि बिहार के लिए धान खरीद का लक्ष्य पिछले तीन वर्षों की औसत खरीद उपलब्धि के आधार पर निर्धारित करने के बजाय राज्य के अनुमानित धान उत्पादन को आधार बनाकर निर्धारित किया जाए। इससे अधिक से अधिक किसानों को अपनी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। मंत्री ने बताया कि बिहार में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जन वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिए प्रतिवर्ष लगभग 33.16 लाख मीट्रिक टन चावल की आवश्यकता होती है, जो लगभग 48.87 लाख मीट्रिक टन धान के बराबर है। बिहार अब स्थानीय स्तर पर आवश्यक मात्रा में धान की खरीद करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि वर्तमान 35 लाख मीट्रिक टन का धान खरीद लक्ष्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा अन्य सरकारी योजनाओं के तहत राज्य की चावल आवश्यकता को देखते हुए पर्याप्त नहीं है। लक्ष्य कम रहने की स्थिति में राज्य के बड़ी संख्या में किसान भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर अपनी उपज बेचने के अवसर से वंचित हो सकते हैं। उन्होंने भारत सरकार से आग्रह किया कि खरीफ विपणन मौसम 2026-27 के लिए बिहार का धान खरीद लक्ष्य 50 लाख मीट्रिक टन निर्धारित करने की आवश्यक स्वीकृति शीघ्र प्रदान की जाए, ताकि राज्य के अधिक से अधिक किसानों को उनकी धान की उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त हो सके और बिहार की खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जा सके।

बिहार में खनिज अन्वेषण और ई-नीलामी को मिलेगी गति, भूमिगत कोयला गैसीकरण की संभावनाओं पर चर्चा

पटना। बिहार में खनिज संसाधनों के वैज्ञानिक अन्वेषण, खनिज ब्लॉकों के विकास और पारदर्शी ई-नीलामी प्रक्रिया को गति देने के उद्देश्य से सोमवार को केंद्रीय कोयला एवं खान राज्यमंत्री सतीश चंद्र दुबे की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें राज्य के खनिज क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में बिहार के खान एवं भूतत्व मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार, विभाग के वरीय अधिकारी, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट, एमईसीएल सहित संबंधित संस्थानों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। भागलपुर जिले में अन्वेषित कोयला ब्लॉक में भूमिगत कोयला गैसीकरण के माध्यम से कोयला संसाधनों के उपयोग की संभावनाओं पर विशेष चर्चा हुई। खान एवं भूतत्व विभाग ने भूमिगत कोयला गैसीकरण से संबंधित प्रस्ताव पर अनुकूलतापूर्वक विचार करने तथा आवश्यक समन्वय और सहयोग उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। केंद्रीय राज्यमंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि बिहार में उपलब्ध खनिज संसाधनों के वैज्ञानिक और आधुनिक तकनीक आधारित उपयोग के लिए केंद्र सरकार आवश्यक सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि भूमिगत कोयला गैसीकरण जैसे विकल्पों की तकनीकी संभावनाओं की समीक्षा कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय राज्यमंत्री ने संभावित निवेशकों और बोलीदाताओं को तकनीकी संभावनाओं से अवगत कराने के लिए पटना में रोड शो आयोजित करने की दिशा में भी पहल करने की बात कही।

बिहार के खान एवं भूतत्व मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार ने कहा कि बिहार की खनिज संपदा राज्य के औद्योगिक और आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण आधार है। सरकार का प्रयास है कि खनिज संसाधनों का वैज्ञानिक, पारदर्शी और सतत उपयोग हो तथा अन्वेषण से लेकर ई-नीलामी और उत्पादन तक की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए। बैठक में खनिज अन्वेषण कार्यों में तेजी लाने के उपायों पर भी चर्चा हुई। जीएसआई के अलावा अधिसूचित निजी अन्वेषण एजेंसियों के माध्यम से विभिन्न खनिजों का व्यापक अन्वेषण कराने की आवश्यकता पर विचार किया गया। ग्लूकोनाइट और लाइमस्टोन सहित प्रमुख खनिजों से जुड़े ब्लॉकों की ई-नीलामी की प्रगति तथा आगामी कार्ययोजना की भी समीक्षा की गई।

संवैधानिक संस्थाओं पर बेबुनियाद आरोप लगाना बंद करे कांग्रेस : डॉ. निहोरा प्रसाद यादव

पटना। जनता दल यूनाईटेड (जदयू) के प्रदेश प्रवक्ता डॉ: निहोरा प्रसाद यादव ने सोमवार को बयान जारी कर कहा कि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और निर्वाचन आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं पर बिना ठोस तथ्य एवं प्रमाण के आरोप लगाना लोकतांत्रिक और संवैधानिक मर्यादाओं के खिलाफ है। राजनीतिक दलों को अपनी असहमति दर्ज कराने का पूरा अधिकार है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते समय तथ्यों और प्रमाणों को सार्वजनिक करना भी उतना ही जरुरी होता है।

उन्होंने कहा कि एसआईआर को लेकर विपक्ष की ओर से निर्वाचन आयोग के आयुक्तों के बीच कथित मतभेद के जो दावे किए गए, उनके संदर्भ में मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों की ओर से जारी सार्वजनिक स्पष्टीकरण के बाद स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि आज जो पार्टी निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रही है, उसे अपने शासनकाल के दौरान संवैधानिक एवं चुनावी संस्थाओं से जुड़े निर्णयों और नियुक्तियों के इतिहास को भी याद करना चाहिए। अगर इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो कांग्रेस ने अपने शासनकाल के दौरान ऐसे मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जो कांग्रेस पार्टी के प्रति ज्यादा जिम्मेदार रहे, जनता के प्रति कम।

इसका प्रमाण है कि कई चुनाव आयुक्तों को रिटायरमेंट के बाद कांग्रेस ने राज्यपाल बनाया, केंद्र में मंत्री बनाया और अपने टिकट पर चुनाव लड़वाया। कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने लोकतंत्र एवं संविधान के साथ घिनौना मजाक करने का काम किया, उस पार्टी द्वारा निष्पक्षता के साथ काम कर रहे आयोग के खिलाफ भ्रम फैलाने की कोशिश की गई। कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करने का असर लोकतांत्रिक व्यवस्था में आम नागरिक के भरोसे पर पड़ता है। उन्होंने विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा कि विपक्ष को आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति की बजाए तथ्य, प्रमाण की राजनीति करनी चाहिए। लोकतंत्र में सवाल पूछने का अधिकार सबको है, लेकिन महज राजनीतिक फायदे के लिए अनर्गल आरोप लगाने को जायज नहीं ठहराया जा सकता।

50 से अधिक महिला स्वच्छताकर्मी हुईं सम्मानित

पूर्णिया,एजेंसी। शहर को स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ बनाए रखने में प्रतिदिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिला स्वच्छताकर्मियों के सम्मान में सोमवार को मधुबनी स्थित सावित्री उत्सव विवाह भवन, प्रताप नगर में 'महिला स्वच्छताकर्मी सम्मान समारोह-2026' का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन ब्रेन डिस्कवरी पब्लिक स्कूल, पूर्णिया की ओर से किया गया। समारोह का उद्देश्य उन महिलाओं के श्रम, समर्पण और सामाजिक योगदान को सम्मान देना था, जो नगर निगम अथवा अन्य माध्यमों से मोहल्लों, सड़कों, बाजारों और सार्वजनिक स्थलों की साफ-सफाई में प्रतिदिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

कार्यक्रम में 50 से अधिक महिला स्वच्छताकर्मियों को सम्मानित किया गया। अतिथियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों के सदस्यों ने उन्हें शॉल ओढ़ाकर, माला पहनाकर, वस्त्र, मास्क एवं सम्मान-पत्र प्रदान कर उनके योगदान के प्रति आभार जताया। वक्ताओं ने कहा कि शहर की स्वच्छता केवल व्यवस्था का विषय नहीं, बल्कि स्वस्थ समाज की बुनियाद है और इसे धरातल पर साकार करने में स्वच्छताकर्मियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में मारवाड़ी महिला मोर्चा की 25 से अधिक सदस्यों ने विशेष रूप से भागीदारी की और महिला स्वच्छताकर्मियों को सम्मानित किया। आयोजन में मारवाड़ी महिला मोर्चा, श्रीराम सेवा संघ, प्रसार भारती, प्रेस क्लब पूर्णिया सहित कई सामाजिक एवं सेवाभावी संस्थाओं का सहयोग रहा। इन संस्थाओं के प्रतिनिधियों और सदस्यों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर स्वच्छता के क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं का उत्साह बढ़ाया। इस पूरे आयोजन को सफल बनाने में ब्रेन डिस्कवरी पब्लिक स्कूल के सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं, कर्मचारियों एवं सदस्यों ने लगातार मेहनत कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम की तैयारी से लेकर स्वच्छताकर्मियों के स्वागत, सम्मान एवं व्यवस्थाओं तक विद्यालय परिवार के सदस्यों ने सक्रिय सहयोग दिया। आयोजन की सफलता में उनकी टीम भावना और समर्पण स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। ब्रेन डिस्कवरी पब्लिक स्कूल के निदेशक अनिकेत कुमार सिंह ने कहा कि संस्था शिक्षा के साथ-साथ सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन करती रही है। उन्होंने कहा कि समाज के लिए निरंतर परिश्रम करने वाले लोगों को सम्मान और पहचान मिलना आवश्यक है। स्वच्छताकर्मी बिना किसी दिखावे के प्रतिदिन शहर को साफ रखने में योगदान देते हैं, इसलिए उनका सम्मान पूरे समाज के श्रम और सेवा भावना का सम्मान है। वक्ताओं ने कहा कि स्वच्छता अभियान की सफलता तभी संभव है, जब सफाईकर्मियों के श्रम के प्रति समाज में सम्मान का भाव हो और प्रत्येक नागरिक स्वयं भी स्वच्छता की जिम्मेदारी निभाए। कार्यक्रम का संदेश 'स्वच्छ शहर, स्वस्थ समाज, सम्मानित महिलाएं' तथा 'स्वच्छता की शक्ति, समाज का सम्मान, नारी का गौरव' रहा। समारोह में सम्मान पाकर महिला स्वच्छताकर्मियों के चेहरों पर खुशी और आत्मसम्मान साफ दिखाई दिया।

बिहार में एक घंटे के विशेष अभियान में 47,958 वाहनों की जांच, 750 से अधिक गिरफ्तार

पटना,एजेंसी। बिहार में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए गृह विभाग के प्रधान सचिव के निर्देश पर राज्यव्यापी विशेष समकालीन अभियान चलाया गया। बिहार पुलिस, रेल पुलिस तथा मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की ओर से चलाए गए इस अभियान का नेतृत्व संबंधित जिलों में पुलिस अधीक्षक (एसपी) और अनपमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) ने किया। रविवार की रात 9 से 10 बजे तक चले एक घंटे के अभियान के दौरान राज्यभर में व्यापक गश्ती, वाहन जांच और त्वरित कार्रवाई की गई। कुल 47,958 वाहनों की जांच की गई और 750 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया।

अभियान के दौरान पटना, नालंदा, गयाजी, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, मोतिहारी, बेतिया, बगहा, सारण और सीवान समेत अन्य जिलों में कार्रवाई की गई। पुलिस ने वाहन जांच के साथ वांछित और वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी, अवैध शराब तथा मादक पदार्थों की बरामदगी पर विशेष ध्यान दिया। जिला पुलिस की ओर से चलाए गए अभियान में 47,718 वाहनों की जांच की गई। यातायात नियमों के उल्लंघन के मामलों में 3,660 वाहनों से कुल 56,00,054 रुपये की राशि वसूल की गई। कार्रवाई के दौरान 110 वाहन जब्त किए गए। पुलिस ने 736 अभियुक्तों और 116 वारंटियों को गिरफ्तार किया। शराब के नशे में पाए गए 29 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया।

अभियान के दौरान अवैध शराब और मादक पदार्थों की भी बड़ी मात्रा में बरामदगी हुई। पुलिस ने 1,169.63 लीटर देशी शराब, 3,482.482 लीटर विदेशी शराब, 216 ग्राम स्मैक, 3.17 ग्राम हेरोइन और 3.37 किलोग्राम गांजा जब्त किया। इसके अलावा चार हथियार, एक कारतूस, 54 मोबाइल फोन और 9,31,500 रुपये नकद भी बरामद किए गए। रेल पुलिस ने भी अपने क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया। इस दौरान 240 वाहनों की जांच की गई। कार्रवाई में नौ अभियुक्तों और एक वारंटी को गिरफ्तार किया गया। रेल पुलिस ने 55.3 लीटर देशी शराब, 205.13 लीटर विदेशी शराब, छह मोबाइल फोन और दो चाकू बरामद किए। पटना में मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने भी अभियान चलाकर 131 दुकानों की जांच की। गांधी मैदान क्षेत्र से 74 लीटर आईएमएफएल, एक ऑटो, एक बुलेट, एक स्कूटी, 50 एटीएम, पासबुक एवं चेकबुक तथा दो मोबाइल फोन बरामद किए गए। कोतवाली क्षेत्र से 280 ग्राम गांजा और दो मोबाइल फोन, जबकि शास्त्रीनगर क्षेत्र से 37 पीस सिगरेट, गांजा और सात पीस गोगो बरामद किए गए। इन कार्रवाइयों में कुल चार लोगों को गिरफ्तार किया गया। जब्त 50 एटीएम से जुड़ी संभावित आर्थिक आपराधिक गतिविधियों की सघन जांच के लिए साइबर इकाई को निर्देश दिया गया है। इसके जरिए एटीएम के इस्तेमाल और उससे जुड़े लेनदेन की जानकारी जुटाई जाएगी। राज्यव्यापी अभियान के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ अवैध शराब और मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने तथा वांछित एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी पर जोर दिया गया। गृह विभाग की ओर से अभियान की निगरानी की गई। जिला पुलिस, रेल पुलिस तथा मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के समन्वित प्रयास से अलग-अलग क्षेत्रों में कार्रवाई की गई। गृह विभाग के प्रधान सचिव ने संबंधित सभी इकाइयों को इस तरह के अभियान को प्रभावी ढंग से जारी रखने तथा अवैध गतिविधियों के खिलाफ नियमानुसार त्वरित एवं सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। अभियान के दौरान सामने आए मामलों में आगे की कानूनी कार्रवाई संबंधित एजेंसियों द्वारा की जा रही है।

बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने दिया इस्तीफा, रामवचन राय ने संभाला कार्यकारी सभापति का पद

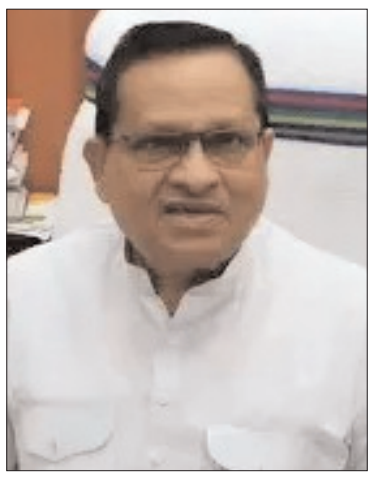

पटना। बिहार विधान परिषद के सभापति और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता अवधेश नारायण सिंह ने सोमवार देर शाम अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद उपसभापति और जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के विधान पार्षद रामवचन राय ने कार्यकारी सभापति के रूप में जिम्मेदारी संभाल ली। पद छोड़ने के बाद अवधेश नारायण सिंह ने कहा कि उन्हें पार्टी का फैसला स्वीकार है और उन्हें किसी तरह का गिला-शिकवा नहीं है। पार्टी ने उन्हें चार बार विधान परिषद का सभापति बनने का अवसर दिया। उन्होंने कहा कि आगे पार्टी की ओर से जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी, उसका वे निर्वहन करेंगे। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान विधान परिषद के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग के लिए आभार भी जताया।

अवधेश नारायण सिंह के इस्तीफे के तुरंत बाद रामवचन राय ने कार्यकारी सभापति का पद संभाला। उन्होंने अवधेश नारायण सिंह के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि वे मिली जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाने का प्रयास करेंगे। रामवचन राय लंबे समय से बिहार विधान परिषद से जुड़े हैं और वर्तमान में जदयू के विधान पार्षद हैं। उनका मौजूदा विधान परिषद कार्यकाल 16 मार्च 2027 तक है। रामवचन राय 83 वर्ष के हैं और उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में माना जाता है। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के साथ की थी। वर्ष 2004 में लालू प्रसाद यादव ने उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाया था। इसके बाद वर्ष 2011 में वे जदयू के विधान पार्षद बने और बाद में विधान परिषद के उपसभापति की जिम्मेदारी भी संभाली। अवधेश नारायण सिंह के इस्तीफे को भाजपा और जदयू के बीच सत्ता-साझेदारी की व्यवस्था से जोड़कर देखा जा रहा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में प्रमुख विधायी पदों के बंटवारे को लेकर यह समझ बनी है कि यदि विधानसभा अध्यक्ष का पद भाजपा के पास रहता है तो विधान परिषद के सभापति का पद जदयू को दिया जाएगा। इसी व्यवस्था के तहत परिषद के सभापति पद पर जदयू की दावेदारी सामने आई थी।

एक नजर

एशियन गेम्स 2026 : बरेका के रोहित यादव ने जैवलिन थ्रो में जीता कांस्य

वाराणसी,एजेंसी। जापान के आइची-नागोया में आयोजित एशियन गेम्स 2026 में बनारस रेल इंजन कारखाना (बरेका) के अंतरराष्ट्रीय जैवलिन थ्रो खिलाड़ी रोहित यादव ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए कांस्य पदक हासिल किया। उनकी इस उपलब्धि से देश के साथ-साथ बरेका का गौरव बढ़ा है। रोहित की सफलता पर बरेका परिवार में हर्ष और उत्साह का माहौल है। रोहित यादव बरेका के इलेक्ट्रिक विभाग में कार्यालय अधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। वह वर्ष 2018 से बरेका में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। विभागीय दायित्वों के निर्वहन के साथ उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जैवलिन थ्रो में अपनी प्रतिभा का लगातार प्रदर्शन किया और देश के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धियां हासिल कीं। रोहित यादव की इस उपलब्धि पर बरेका के महाप्रबंधक आशुतोष पंत, खेल संघ के पदाधिकारियों तथा समस्त बरेका परिवार ने उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं। महाप्रबंधक ने उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि रोहित ने अपने खेल कौशल से बरेका और देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने रोहित के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए आगामी प्रतियोगिताओं में भी बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दीं। उल्लेखनीय है कि एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने सोमवार को एक दिन में सर्वाधिक आठ पदक अपने नाम किए। हालांकि, इनमें कोई स्वर्ण पदक शामिल नहीं रहा। इससे पहले शनिवार और रविवार को भारत ने एक-एक दिन में सात-सात पदक जीते थे। भारतीय खिलाड़ियों ने निशानेबाजी, एथलेटिक्स, कुराश और भाला फेंक में पदक हासिल किए। सोमवार को मिले आठ पदकों में चार रजत और चार कांस्य पदक शामिल रहे। इस प्रदर्शन के साथ भारत के कुल पदकों की संख्या 45 हो गई है और वह पदक तालिका में 12वें स्थान पर है।

धोनी की शांत कप्तानी ने मुझे प्रभावित किया: सुभ्रांशु सेनापति

नई दिल्ली,एजेंसी। ओडिशा टी20 लीग की फ्रेंचाइजी टीम केओंझर माइनर्स के कप्तान सुभ्रांशु सेनापति ने टूर्नामेंट में मिली एक और शानदार जीत को शान्त रवैये और संयम के तरीके की जीत बताया। उन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के शान्त चित्त होकर रणनीतियों पर काम करने की योजना की तारीफ की और उसे ही अपनी प्रेरणा बताई। टूर्नामेंट में एक और जीत के बाद सेनापति ने कहा कि शुरुआती मैच में हार के बाद टीम पर दबाव था, लेकिन खिलाड़ियों ने खुद पर भरोसा बनाए रखा। वरिष्ठ खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ के सहयोग से टीम ने लय हासिल की है। उन्होंने कहा कि उनकी टीम संतुलित है और अलग-अलग परिस्थितियों में पांच, 10 या 20 ओवर के मैच खेलने के लिए तैयार है। चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) में रहते हुए एमएस धोनी की कप्तानी और उनके शांत रवैये को बड़ी प्रेरणा बताते हुए कहा कि वो मानते हैं कि दबाव के समय शांत रहने से फैसले लेने के लिए ज्यादा विकल्प मिलते हैं। कप्तान के तौर पर धोनी के फैसलों को बारिकी से समझने को लेकर उन्होंने कहा कि माही सर के शांत स्वभाव ने उन्हें शुरू से प्रभावित किया। सेनापति के मुताबिक, धोनी किसी भी परिस्थिति में आखिरी तक मैच नहीं छोड़ते और मैदान पर उनकी योजना बनाने का तरीका अलग है। सेनापति ने इस टूर्नामेंट को युवा खिलाड़ियों के लिए भी अहम बताया। उन्होंने कहा कि प्रसारण के कारण जिला स्तर के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा बड़े दर्शकों के सामने दिखाने का मौका मिल रहा है।

बारिश के बीच पिथौरागढ़ हरिकेन्स और टिहरी टाइटंस की जीत

देहरादून। उत्तराखंड प्रीमियर लीग (यूपीएल) 2026 में सोमवार को बारिश से प्रभावित मुकाबलों में पिथौरागढ़ हरिकेन्स और टिहरी टाइटंस ने शानदार जीत दर्ज की। पिथौरागढ़ ने नैनीताल टाइगर्स को डकवर्थ-लुईस-स्टर्न (डीएलएस) नियम से 27 रन से हराया, जबकि टिहरी ने ऋषिकेश रिवर किंग्स को नौ विकेट से शिकस्त दी। पहले मुकाबले में पिथौरागढ़ हरिकेन्स ने 14 ओवर में सात विकेट पर 159 रन बनाए। आंजनेय सूर्यवंशी ने 24 गेंदों में 73 और समर्थ सेमवाल ने 25 गेंदों में 44 रन की तेज पारियां खेलीं। नैनीताल की ओर से अदी खान ने पांच विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए नैनीताल टाइगर्स 6.1 ओवर में तीन विकेट पर 41 रन ही बना सकी थी कि बारिश के कारण खेल रोकना पड़ा। दोबारा खेल शुरू नहीं होने पर डीएलएस नियम के तहत पिथौरागढ़ को 27 रन से विजेता घोषित किया गया। सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पिथौरागढ़ की यह लगातार तीसरी जीत है। दूसरे मुकाबले को बारिश के कारण पांच-पांच ओवर का कर दिया गया। ऋषिकेश रिवर किंग्स ने चार विकेट पर 73 रन बनाए। दीक्षांशु नेगी ने आठ गेंदों में 26 रन बनाए। टिहरी टाइटंस ने 74 रन के लक्ष्य को 4.5 ओवर में एक विकेट खोकर हासिल कर लिया। कप्तान विजय शर्मा ने 17 गेंदों में नाबाद 56 रन की विस्फोटक पारी खेली और टीम को नौ विकेट से जीत दिलाई।

एशियन खेल : भारत ने सोमवार को जीते आठ पदक, पदक तालिक में 12वें स्थान पर

नई दिल्ली। एशियन खेल-2026 में 28 सितंबर का दिन भारत के लिए पदकों के लिहाज से शानदार रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने सोमवार को कुल आठ पदक अपने नाम किए, जिसमें चार रजत और चार कांस्य पदक शामिल हैं। दिन का सबसे अहम प्रदर्शन निशानेबाज ईशा सिंह, एथलीट गुलवीर सिंह, मुरली श्रीशंकर और भाला फेंक खिलाड़ी यशवीर सिंह का रहा, जिन्होंने रजत पदक जीते। ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। वह स्वर्ण पदक के लिए चीन की शियाओ जियारुइशुआन के खिलाफ शूट-ऑफ तक पहुंचीं, लेकिन निर्णायक मुकाबले में मामूली अंतर से पीछे रह गईं। कुराश में पिंकी बलहारा ने महिलाओं के 78 किग्रा वर्ग में कांस्य पदक जीता। पिंकी को सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया की सुमिन मो के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। एथलेटिक्स में भारत को कई पदक मिले। गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय 3:36.72 सेकंड के साथ रजत पदक जीता। वहीं मुरली श्रीशंकर ने पुरुषों की लंबी कूद में 8.07 मीटर की छलांग लगाकर रजत पदक अपने नाम किया। विथ्या रामराज ने महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में 54.75 सेकंड के राष्ट्रीय रिकॉर्ड समय के साथ कांस्य पदक जीता। पारुल चौधरी ने महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में 15:14.61 सेकंड के समय के साथ कांस्य पदक हासिल किया। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में भारत ने दो पदक जीते। यशवीर सिंह ने 85.72 मीटर की व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ रजत और रोहित यादव ने 84.35 मीटर के प्रयास के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। श्रीलंका के रुमेश पाथिरागे ने 88.55 मीटर की थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता।

इन पदकों के साथ भारत की कुल पदक संख्या 45 हो गई है। भारत के खाते में अब चार स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य पदक हैं और वह पदक तालिका में 12वें स्थान पर है। चीन 130 स्वर्ण, 53 रजत और 45 कांस्य समेत कुल 228 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। मेजबान जापान 41 स्वर्ण, 68 रजत और 62 कांस्य समेत 171 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है। दक्षिण कोरिया 21 स्वर्ण, 26 रजत और 43 कांस्य समेत 90 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। उज्बेकिस्तान 12 स्वर्ण, 17 रजत और 13 कांस्य समेत 42 पदकों के साथ चौथे, जबकि कजाकिस्तान 9 स्वर्ण, 13 रजत और 23 कांस्य समेत 45 पदकों के साथ पांचवें स्थान पर है।

एशियन खेल : सूरज करकेरा के 100 अंतरराष्ट्रीय मैच पूरे, हॉकी इंडिया ने दी बधाई

काकामिगाहारा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर सूरज करकेरा ने अपने करियर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए 100 सीनियर अंतरराष्ट्रीय मुकाबले पूरे कर लिए। उन्होंने यह उपलब्धि जापान में जारी एशियन खेल-2026 में सोमवार को बांग्लादेश के खिलाफ भारत के पांचवें पूल ए मुकाबले के दौरान हासिल की।

30 वर्षीय सूरज ने 2017 में सीनियर अंतरराष्ट्रीय पदार्पण किया था और इसके बाद से वह भारतीय टीम की गोलकीपिंग इकाई का अहम हिस्सा रहे हैं। उन्होंने कई प्रमुख अंतरराष्ट्रीय और महाद्वीपीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। सूरज के प्रमुख उपलब्धियों में 2017 एशिया कप का स्वर्ण पदक शामिल है। इसके बाद उन्होंने 2021 एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में कांस्य पदक जीता। वह 2022 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम का भी हिस्सा रहे। 2023 में उन्होंने हॉकी 5एस एशिया कप में भारत के स्वर्ण पदक अभियान में योगदान दिया। सूरज ने 2024 एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा रहते हुए एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। इसके बाद 2025 एशिया कप में भी उन्होंने भारत की स्वर्ण पदक विजेता टीम में अपनी भूमिका निभाई। एशियन खेल में भारत के खिताब बचाने के अभियान के दौरान 100 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले पूरे करना सूरज के करियर का एक खास पड़ाव है। यह उपलब्धि भारतीय हॉकी के लिए उनके लंबे समय से किए जा रहे योगदान, निरंतरता और प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टिर्की ने सूरज को बधाई देते हुए कहा, 'भारत के लिए 100 सीनियर अंतरराष्ट्रीय मुकाबले पूरे करने की शानदार उपलब्धि हासिल करने पर सूरज को हार्दिक बधाई। गोलकीपर के रूप में सूरज ने जब भी टीम को उनकी जरूरत पड़ी, शानदार संयम और प्रतिबद्धता दिखाई है। मुझे विश्वास है कि वह टीम के लिए इसी तरह महत्वपूर्ण योगदान देते रहेंगे। हॉकी इंडिया के महासचिव भोला नाथ सिंह ने भी सूरज की उपलब्धि की सराहना की। उन्होंने कहा, 'भारत की सीनियर टीम के लिए 100 मुकाबले पूरे करना सूरज और भारतीय हॉकी के लिए गर्व का क्षण है। यह उपलब्धि उनके पूरे करियर में दिखाई देने वाली कड़ी मेहनत, अनुशासन और दृढ़ता को दर्शाती है।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका की प्रारंभिक टीम में रबाडा शामिल

जोहान्सबर्ग। दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 अक्टूबर से शुरू होने वाली तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए अपनी प्रारंभिक टीम में तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा को शामिल किया है। हैमस्ट्रिंग चोट से उबर रहे रबाडा की पहले टेस्ट में उपलब्धता का फैसला अगले सप्ताह होने वाले इंट्रा-स्क्वाड मुकाबले के बाद किया जाएगा। रबाडा को विंटर ट्रेनिंग के दौरान हैमस्ट्रिंग चोट लगी थी और वह फिलहाल उससे उबर रहे हैं। लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमैन और क्वेना मफाका को हैमस्ट्रिंग चोटों से उबरने के कारण टीम में जगह नहीं मिली है।

केंद्रीय अनुबंध से बाहर हो चुके एनरिक नॉर्त्जे को विस्तारित टीम में शामिल किया गया है। वह मार्च, 2023 के बाद अपना पहला टेस्ट खेलने की दौड़ में हैं। टीम में कुल सात तेज गेंदबाजों को जगह दी गई है। जेराल्ड कोएत्जी भी टीम का हिस्सा हैं, जिन्होंने पिछले सप्ताह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे से चोट के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की थी। उन्होंने आखिरी टेस्ट नवंबर, 2024 में खेला था। कोएत्जी के अलावा कॉर्बिन बॉश, मार्को यानसन, वियान मुल्डर और डेन पैटरसन तेज गेंदबाजी के विकल्प होंगे।

पैटरसन विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए दक्षिण अफ्रीकी टीम का हिस्सा थे। शीर्ष क्रम के बल्लेबाज मार्क्स एकरमैन टीम में एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अभी तक टेस्ट डेब्यू नहीं किया है। दक्षिण अफ्रीका ए के लिए 1000 से अधिक रन बना चुके एकरमैन शीर्ष तीन में जगह बनाने के लिए टोनी डी जॉर्जी, ट्रिस्टन स्टब्स और वियान मुल्डर के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे। स्पिन विभाग में केशव महाराज, साइमन हार्मर और सेनुरन मुथुसामी को शामिल किया गया है। तीनों खिलाड़ी पिछले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र में दक्षिण अफ्रीका के लिए खेल चुके हैं। शुरुआती सीजन में परिस्थितियां स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार रहने की उम्मीद है और तीनों टेस्ट समुद्र तटीय मैदानों पर खेले जाने हैं। ऐसे में दक्षिण अफ्रीका एकादश में तीन में से दो स्पिनरों को उतारने पर विचार कर सकता है। दक्षिण अफ्रीका की टेस्ट टीम 1 अक्टूबर को डरबन में एकत्र होगी।

एचपीसीए एजीएम : क्रिकेट को जिला स्तर पर मजबूत करने पर रहेगा फोकस

धर्मशाला,एजेंसी। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (एचपीसीए) की वार्षिक आम बैठक में आगामी 2026-27 सत्र में क्रिकेट को ज़िला स्तर पर और अधिक मजबूत करने पर जोर दिया गया है। इस दौरान जिला स्तर पर युवा और आयु-वर्ग क्रिकेट के रास्तों को मज़बूत करने, धर्मशाला के बाहर भी हाई-परफ़ॉर्मेंस सहायता का विस्तार करने, मैदानों की सुविधाओं के उन्नयन और हिमाचल में लड़कों और लड़कियों की भागीदारी बढ़ाने पर एचपीसीए का फोकस रहेगा। सोमवार को बीती रात धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित एचपीसीए की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में यह निर्णय लिए गए। बैठक में पदाधिकारियों और सदस्यों ने उस ऐतिहासिक सत्र की समीक्षा की, जिसमें धर्मशाला ने पहली बार आईपीएल क्वालीफ़ायर मुकाबले की मेज़बानी की। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और पूरे हिमाचल में खेल की बढ़ती पहुंच पर भी चर्चा हुई। 2025-26 सत्र के दौरान एचपीसीए स्टेडियम ने टाटा आईपीएल के चार मुकाबलों की मेज़बानी की, जिनमें एक क्वालीफ़ायर मुकाबला भी शामिल था। यह पहला अवसर था जब धर्मशाला में आईपीएल प्लेऑफ़ मुकाबला खेला गया, जो स्टेडियम और प्रदेश के क्रिकेट के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। वर्ष के दौरान स्टेडियम ने भारत बनाम अफ़गानिस्तान एकदिवसीय मुकाबले की भी मेज़बानी की। स्टेडियम की नई स्मार्ट सुविधाओं, जैसे डिजिटल टिकटिंग और पूरे स्टेडियम में वाई-फ़ाई, से दर्शकों को मैच के

दिन बेहतर अनुभव मिला। स्टेडियम के बाहर, चंबा और मंडी में आयोजित आईपीएल फ़ैन पार्क ने टूर्नामेंट का रोमांच प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचाया। ज़मीनी स्तर पर एचपीसीए के सब-सेंटर नेटवर्क का हिमाचल प्रदेश के सभी ज़िलों में विस्तार जारी रहा। इससे युवा लड़के-लड़कियों को अपने घर के पास ही कोचिंग, सुविधाएं और प्रतिस्पर्धी क्रिकेट का अवसर मिल रहा है। पूरे सत्र में आयोजित ज़िला स्तरीय और आयु-वर्ग प्रतियोगिताओं ने उभरती प्रतिभाओं को खेल के ऊंचे स्तरों तक पहुंचने का निरंतर मंच प्रदान किया।

मैदान पर भी हिमाचल के खिलाड़ियों ने अपनी छाप छोड़ी। सुषमा वर्मा और हरलीन देओल का कैरेबियन प्रीमियर लीग के लिए चयन प्रदेश के लिए गर्व का क्षण रहा और यह हिमाचल के युवा क्रिकेटरों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। एसोसिएशन ने धर्मशाला में स्थापित नए सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस का भी उल्लेख किया, जहां कोचिंग, स्पोर्ट्स मेडिसिन, पुनर्वास और परफ़ॉर्मेंस एनालिसिस की सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं। वर्ष के दौरान एचपीसीए के कोचों, अंपायरों, मैच अधिकारियों और चिकित्सा कर्मियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और नियुक्तियां भी मिलीं, जिससे प्रदेश का क्रिकेट तंत्र और मज़बूत हुआ है। बैठक में अनुराग सिंह ठाकुर, मानद सचिव मनुज शर्मा, मानद उपाध्यक्ष विजय भंडारी, मानद कोषाध्यक्ष विक्रम सिंह, मानद संयुक्त सचिव विशाल शर्मा तथा एसोसिएशन के सदस्य उपस्थित रहे।

कोहली का करियर खत्म होने के बाद ही उनकी विरासत की अहमियत समझ आएगी : इयान बिशप

नई दिल्ली,एजेंसी। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज के पहले मुकाबले में आठ विकेट से शानदार जीत दर्ज कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। इस मुकाबले में विराट कोहली ने एकदिवसीय क्रिकेट में 15,000 रन पूरे किए। उनके इस ऐतिहासिक मुकाम और शानदार निरंतरता पर जियोस्टार के विशेषज्ञ इयान बिशप और वरुण आरोन ने जियोहॉटस्टार के 'हायर क्रिकेट लाइव' पर चर्चा की।

इयान बिशप ने विराट कोहली की 15,000 एकदिवसीय रन की उपलब्धि की सराहना करते हुए कहा, 'आपको वही करना पसंद होना चाहिए, जो आप इतने लंबे समय तक करते हैं और उसी के साथ खुद को विकसित करते हैं। मुझे लगता है कि यह उन्हें एक बेहद खास श्रेणी में रखता है, क्योंकि उन्होंने महान सचिन तेंदुलकर की तुलना में 74 पारियां कम खेलकर 15,000 रन पूरे किए हैं। मैं सचिन को बहुत सम्मान देता हूं और उनके खिलाफ खेल चुका हूं। उनका करियर जहां भी खत्म होगा, उन्हें इस प्रारूप के महानतम बल्लेबाजों में, बल्कि शायद सबसे महान बल्लेबाजों में शामिल होना ही होगा। यह असाधारण है। उन्होंने आगे कहा, 'टेलीविजन पर और स्टेडियम में मौजूद कई प्रशंसक इसकी सराहना कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम इसकी पूरी अहमियत तब तक समझ पाएंगे, जब तक उनके खेलने के दिन खत्म हुए कुछ समय

नहीं बीत जाता। कोहली की निरंतरता पर बिशप ने कहा, 'विराट इस मामले में अलग हैं। रनों के लिए उनकी भूख और लक्ष्य का पीछा करते समय उनकी गणना, मुझे लगता है कि इस खेल में उसका कोई मुकाबला नहीं है।

विराट को मौके की अहमियत समझने की क्षमता है, भले ही वह खुद इसे स्वीकार न करें। लेकिन यही उनका विकास है। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि उन्होंने 15,000 रन पूरे कर लिए हैं। मुझे पता है कि सचिन भी वहां पहुंचे थे, लेकिन यह बहुत बड़ी संख्या है। अगर इस समय मेरे पास फूल होते, तो मैं उन्हें देता, क्योंकि वह वास्तव में इसके हकदार हैं। युवा पीढ़ी को कोहली से सीख लेने की बात पर बिशप ने कहा, 'हम सभी इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि मैं खिलाड़ियों को यह कहते सुन-सुनकर थक गया हूं कि 'मैं इसी तरह खेलता हूं।' खेल से बाहर के लोग भी कहते हैं कि एक निश्चित उम्र के बाद आप नई चीजें नहीं सीख सकते। अगर मुझे विराट कोहली के वर्षों के प्रदर्शन से एक चीज सीखनी हो, तो वह यह है कि आक्रामक खेल को विकसित करने, टी20 या सफेद गेंद के क्रिकेट में आए बदलावों के अनुसार खुद को ढालने, अपने पावर गेम को विकसित करने और अपनी उम्र में इतने छक्के लगाने के लिए कभी देर नहीं होती। उन्होंने कहा, 'यह दिखाता है कि जब इच्छाशक्ति हो, तो कई बार अगर आप पर्याप्त समझदार हैं तो रास्ता खोज सकते हैं। अगर कोई क्रिकेटर इससे कुछ सीख सकता है, तो मैं चाहता हूं कि वह यही याद रखे—अपने सहज क्षेत्र में मत रुको। बल्लेबाज, गेंदबाज, क्षेत्ररक्षक या कप्तान, अपने सहज क्षेत्र से बाहर निकलो। वरुण आरोन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 4/40 का शानदार प्रदर्शन करने वाले कुलदीप यादव की तारीफ की।

सचिन तेंदुलकर ने ओपनएआई के साथ की साझेदारी की घोषणा

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने सोमवार को ओपनएआई के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की। तेंदुलकर ने कहा कि वह चैटजीपीटी के साथ नई संभावनाओं को तलाशने, अपने अनुभव साझा करने और अधिक लोगों को इस तकनीक को आजमाने के लिए प्रोत्साहित करने को लेकर उत्साहित हैं।

तेंदुलकर ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट के जरिए इस साझेदारी की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि इस साझेदारी के तहत वह चैटजीपीटी के इस्तेमाल के नए तरीके तलाशेंगे और जो चीजें उन्हें उपयोगी लगेंगी, उन्हें लोगों के साथ साझा करेंगे। सचिन तेंदुलकर ने कहा, 'मैं ओपनएआई के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा करते हुए उत्साहित हूं। हमारे पास कुछ दिलचस्प चीजें आने वाली हैं और मैं उन्हें आपके साथ साझा करने का इंतजार नहीं कर सकता। मैं हमेशा से जिज्ञासु रहा हूं... एक सवाल अक्सर दूसरे सवाल की ओर ले जाता है और चैटजीपीटी ने निश्चित रूप से इस आदत को और बढ़ावा दिया है। लेकिन जब मुझे कुछ काम पूरे करने होते हैं, तब भी यह उपयोगी साबित हुआ है, जैसे परिवार के साथ मेरी पिछली यात्रा की योजना बनाना। उन्होंने आगे कहा, 'इसी चीज को लेकर मैं इस साझेदारी के साथ उत्साहित हूं। यह जानना कि मैं चैटजीपीटी के साथ और क्या कर सकता हूं, जो मुझे उपयोगी लगता है उसे साझा करना और अधिक लोगों को इसे आजमाने के लिए प्रोत्साहित करना—ऐसी किसी चीज के साथ जिसकी उन्हें परवाह है। कोई सवाल, कोई विचार, कोई ऐसी चीज जिसे आप हमेशा से तलाशना चाहते थे। शुरुआत करने के लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं। साथ मिलकर इसे तलाशने का इंतजार है। तेंदुलकर ने इस साझेदारी से जुड़ा एक वीडियो भी साझा किया। वीडियो में वह चैटजीपीटी से एक खेल खेलने के लिए कहते हैं और केवल 10 सवालों की मदद से यह अनुमान लगाने को कहते हैं कि वह किसके साथ हैं। चैटजीपीटी 10 सवालों के जरिए सही जवाब तक पहुंच जाता है। क्रिकेट इतिहास के महानतम बल्लेबाजों में शामिल तेंदुलकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने 664 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 34,357 रन बनाए हैं। इसमें टेस्ट में 15,921, एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में 18,426 और एकमात्र टी20 अंतरराष्ट्रीय में 10 रन शामिल हैं। उनके नाम 100 अंतरराष्ट्रीय शतक भी दर्ज हैं। सचिन तेंदुलकर ने 1989 से 2013 तक भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला। वह 2010 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नाबाद 200 रन बनाकर एकदिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने थे। वह 50 अंतरराष्ट्रीय शतक पूरे करने वाले पहले क्रिकेटर भी थे। 2014 में तेंदुलकर को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वह यह सम्मान पाने वाले पहले खिलाड़ी हैं। ओपनएआई के साथ तेंदुलकर की साझेदारी ऐसे समय में हुई है, जब कंपनी चैटजीपीटी के इस्तेमाल को अलग-अलग क्षेत्रों में विस्तार दे रही है।

एक नजर

नेपाल के बागलुंग जिले में बारिश के बाद भूस्खलन, 10 की मौत और एक लापता

काठमांडू,एजेंसी। नेपाल के बागलुंग जिले में लगातार हो रही बारिश के बाद आए भूस्खलन में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति लापता है। बारिश के कारण पिछले दो दिनों में जिले में बड़े पैमाने पर जान-माल का नुकसान हुआ है। रविवार को ही नौ लोगों की मौत हुई, जबकि एक व्यक्ति लापता है। शनिवार को एक व्यक्ति की मौत हुई थी। जिला पुलिस कार्यालय बागलुंग के प्रमुख फणिन्द्र प्रसाईं के अनुसार, रविवार को तमानखोला गांव में चार लोगों की मौत और एक व्यक्ति लापता है। वहीं, निसीखोला गांव में पांच लोगों की मौत हुई है। तमानखोला में एक घर भूस्खलन की चपेट में आने से बुद्धिराज घर्ती (80) और भीमदेवी घर्ती (66) की मौत हो गई। इसी इलाके में भूस्खलन से आठ घर बह गए। इसके अलावा भूस्खलन से घर दबने के कारण हस्तवीर श्रीपाली (50) और उडिसरा श्रीपाली (65) की मौत हो गई। हस्तवीर की पत्नी भूस्खलन के बाद से लापता हैं। इसी तरह, निसीखोला के हदधारा में भूस्खलन से घर दबने के कारण एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान श्याम कुमारी विक (36) और उनके बेटे मनोज (13), मुकेश (8) और निशान विक (3) के रूप में हुई है। वहीं, निसीखोला के रंगिल में भूस्खलन से गोठ (पशुशाला) में दबने के कारण सूर्यबहादुर घर्ती (50) की मौत हुई। इससे एक दिन पहले शनिवार को ताराखोला धस्मर में भूस्खलन से घर दबने के कारण 59 वर्षीय मनबहादुर रोका की मौत हुई थी। बागलुंग के प्रमुख जिला अधिकारी कृष्णप्रसाद आचार्य के अनुसार, पूर्व सूचना मिलने के कारण इससे होने वाली अतिरिक्त मानवीय क्षति को रोका जा सका। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य के लिए नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर सहित सुरक्षा अधिकारियों की टीम पहुंची है।

भारी बारिश से नेपाल के चार जिले सड़क संपर्क से कटे, कई प्रमुख राजमार्ग पूरी तरह बंद

काठमांडू,एजेंसी। नेपाल के बागलुंग, म्याग्दी, मुस्तांग और मनांग जिले केंद्रीय सड़क नेटवर्क से कट गए हैं। गत बुधवार से लगातार हो रही भारी बारिश ने इन जिलों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। बागलुंग, म्याग्दी और मुस्तांग और मनांग को प्रदेश राजधानी पोखरा से जोड़ने वाला सिद्धार्थ राजमार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गया है। सड़क विभाग के अनुसार, सिद्धार्थ राजमार्ग के कुश्मा-मालढुंगा खंड में सहस्त्रधारा के पास करीब 100 मीटर सड़क कालीगंडकी नदी की बाढ़ में बह गई है। इसके कारण तीनों जिले केंद्रीय सड़क नेटवर्क से अलग हो गए हैं। बाढ़ के कारण पर्वत और बागलुंग को जोड़ने वाला मालढुंगा पुल भी क्षतिग्रस्त हुआ है। खास तौर पर पुल के पर्वत की ओर का सड़क हिस्सा बह गया है। इसके साथ ही बागलुंग और पर्वत के बीच सड़क संपर्क भी टूट गया है। इसी तरह, भूस्खलन के कारण बेनी-जोमसोम-कोरला सड़क खंड पूरी तरह बंद है। इससे मुस्तांग का अन्य जिलों से सड़क संपर्क भी टूट गया है। पुलिस के अनुसार, म्याग्दी के बेनी से दरबांग को जाने वाली सड़क भी अवरुद्ध है। बागलुंग में मध्यपहाड़ी राजमार्ग के विभिन्न हिस्से भी बाढ़ में बह गए हैं। सड़क डिविजन के प्रमुख हरिप्रसाद सुवेदी ने बताया कि गोडाबाँधे से गलकोट तक कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ है। उन्होंने बताया कि गलकोट से बुर्तिबांग तक रविवार शाम से एकतरफा यातायात शुरू कर दिया गया है। वहीं, बुर्तिबांग से निसीखोला तक करीब पांच से सात स्थानों पर सड़क बहने की जानकारी मिली है। हालांकि, टीम अभी मौके तक नहीं पहुंच सकी है। सड़क विभाग के अनुसार, कालीगंडकी कॉरिडोर के मालढुंगा-बेनी-जोमसोम-कोरला खंड में 46 स्थानों पर सड़क अवरुद्ध है। ज्यादातर स्थानों पर मलबे के साथ भूस्खलन हुआ है, जबकि कुछ जगह सड़क कट गई है। इसी तरह, कालीगंडकी कॉरिडोर के गैडाकोट-मालढुंगा खंड में आठ स्थानों पर अवरोध है। पूर्वी नवलपरासी के घुमाउरी घाट और बागलुंग के जैमिनी में भी कालीगंडकी कॉरिडोर अवरुद्ध है। सड़क विभाग के अनुसार, विभिन्न स्थानों पर हुए अवरोधों को हटाने और सड़क संपर्क बहाल करने का काम जारी है।

एर्दोगन के खिलाफ आईसीसी में मुकदमा चलाएंगे नेतन्याहू: रिपोर्ट

तेल अवीव। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तुर्किए के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) में मुकदमा चलाने की तैयारी के निर्देश दिए हैं। इजराइली ब्रॉडकास्टर आई24 ने सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी। रिपोर्ट के मुताबिक, नेतन्याहू ने इजराइल के एक अंतर-एजेंसी समूह और अंतरराष्ट्रीय कानून विभाग के निदेशक को एर्दोगन के खिलाफ संभावित आईसीसी मामले की तैयारी शुरू करने को कहा है। प्रस्तावित मामले में कुर्द लोगों के साथ तुर्किए के व्यवहार और हमास को कथित समर्थन तथा फंडिंग से जुड़े आरोपों को शामिल किए जाने की बात कही गई है। आई 24 के अनुसार, यह कदम तुर्किए के न्याय मंत्रालय द्वारा इंटरपोल से नेतन्याहू के खिलाफ 'रेड नोटिस' जारी करने का अनुरोध किए जाने के बाद उठाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल आईसीसी में स्वतंत्र रूप से मामला आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकता है, हालांकि इजराइली अधिकारी किसी तीसरे पक्ष या मध्यस्थ के जरिए प्रक्रिया शुरू करने पर भी विचार कर सकते हैं। इजराइल और तुर्किए दोनों ने रोम संविधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और आईसीसी के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार नहीं किया है। एर्दोगन लंबे समय से इजराइल की गाजा नीति की आलोचना करते रहे हैं। वे गाजा में इजराइली सैन्य कार्रवाई को 'जनसंहार' बताते रहे हैं और हमास के सदस्यों को 'प्रतिरोध सेनानी' कहते हैं। तुर्किए ने हमास के वरिष्ठ नेताओं को राजनीतिक समर्थन देने की बात भी सार्वजनिक रूप से कही है। इजराइली मीडिया ने इससे पहले अगस्त में अमेरिकी राष्ट्रपति के दूत जेरेड कुशनर की इजराइल यात्रा के दौरान नेतन्याहू के साथ हुई चर्चाओं में तुर्किए द्वारा हमास को कथित वित्तीय समर्थन का मुद्दा शामिल होने की रिपोर्ट दी थी। नवंबर, 2024 में आईसीसी ने गाजा में कथित युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपों को लेकर नेतन्याहू और इजराइल के तत्कालीन रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे।

जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए नेपाल में मातृत्व अवकाश में बढ़ोतरी का प्रस्ताव

काठमांडू,एजेंसी। नेपाल की स्वास्थ्य मंत्री निशा मेहता ने कहा है कि जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए मातृत्व अवकाश के जरिए प्रोत्साहन देने का भी प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने सोमवार को प्रतिनिधि सभा में सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार (पहला संशोधन) विधेयक, 2026 पेश करते हुए यह बात कही। विधेयक पेश करते हुए मंत्री मेहता ने कहा, 'नेपाल की नवीनतम जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या वृद्धि दर लगातार घट रही है। इसलिए जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए अवकाश संबंधी प्रोत्साहन सहित अन्य प्रावधानों को कानून में शामिल करना आवश्यक है। मंत्री मेहता ने यह विधेयक 21 सितंबर को प्रतिनिधि सभा में पेश किया था। प्रस्तावित विधेयक के अनुसार सरकारी, गैर-सरकारी या निजी संस्थानों में कार्यरत महिलाओं को प्रसव से पहले और बाद में कुल छह महीने का सवेतन मातृत्व अवकाश मिलेगा। इसके अलावा, जिन पुरुष कर्मचारियों की पत्नी बच्चे को जन्म देती है, उन्हें 42 दिनों का सवेतन पितृत्व अवकाश देने का प्रस्ताव किया गया है।

मौजूदा कानून में माताओं को 90 दिनों का मातृत्व अवकाश मिलता है। नए विधेयक में इसे बढ़ाकर छह महीने करने का प्रस्ताव है। वहीं, पितृत्व अवकाश को मौजूदा 15 दिनों से बढ़ाकर 42 दिन करने का प्रस्ताव किया गया है। मंत्री मेहता ने कहा कि यह विधेयक सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण, सस्ती और सुलभ मातृ एवं प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने तथा महिलाओं के सुरक्षित मातृत्व और प्रजनन

स्वास्थ्य से जुड़े संवैधानिक अधिकारों का सम्मान, संरक्षण और पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भी लाया गया है। विधेयक में प्रसव सेवाएं प्रशिक्षित प्रसव सहायकों के माध्यम से उपलब्ध कराने का प्रावधान भी किया गया है। साथ ही, मातृत्व सेवाएं देने से इनकार करने पर रोक और प्रसव के दौरान महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की हिंसा पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, विशेष परिस्थितियों में गर्भपात से जुड़े प्रावधानों में संशोधन और नए प्रावधान शामिल किए गए हैं। जबरन गर्भपात से संबंधित प्रावधान भी विधेयक में शामिल हैं। प्रस्तावित संशोधनों के तहत नए जोड़े गए कुछ अपराधों को आपराधिक कृत्य माना जाएगा और उनके लिए दंड का प्रावधान किया जाएगा।

अफगानिस्तान का दावा- नूरिस्तान में 28 लड़ाके ढेर, पाकिस्तान पर घुसपैठ में मदद का आरोप

काबुल,एजेंसी। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि रविवार को नूरिस्तान प्रांत में उसके सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 28 लड़ाके मारे गए और 32 घायल हुए। मंत्रालय के अनुसार, यह कार्रवाई पाकिस्तान से आए एक हथियारबंद समूह की सीमा पार घुसपैठ के बाद हुई। अफगान पक्ष ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी मिलिशिया ने घुसपैठ में मदद की थी। बलूचिस्तान की ऑनलाइन समाचार नेटवर्क 'द बलूचिस्तान पोस्ट' के मुताबिक, अफगान रक्षा मंत्रालय ने यह भी आरोप लगाया कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी मदद का हवाला देकर अफगान सेना के पूर्व सैनिकों की भर्ती करती है, उन्हें प्रशिक्षण देती है और बाद में नूरिस्तान की ओर भेजती है। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।

इससे एक दिन पहले, शनिवार को अफगान अधिकारियों ने कहा था कि सीमा सुरक्षा बलों ने कामदेश जिले में डूरंड लाइन के पास घुसपैठ की कोशिश नाकाम करते हुए 10 लड़ाकों को मार गिराया और छह को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने आरोप लगाया था कि अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट (एएफएफ) के कुछ सदस्य इस्लामिक स्टेट के साथ मिलकर काम कर रहे थे। हालांकि, एएफएफ ने इन घटनाओं का अलग विवरण दिया। संगठन के अनुसार, शनिवार सुबह तालिबान बलों ने ड्रोन के जरिए उसके ठिकानों पर हमला किया, जिसके बाद उसके लड़ाकों ने जवाबी कार्रवाई की और कई चेकपोस्ट पर कब्जा कर लिया। एएफएफ ने दावा किया कि तालिबान बल अरंडू और कामदेश के कुछ हिस्सों से पीछे हटकर पड़ोसी कुनार प्रांत के नारी जिले की ओर चले गए। लड़ाई के बाद सामने आए कुछ वीडियो में हिरासत में लिए गए लोगों ने कथित तौर पर बताया कि उन्हें ईरान से पाकिस्तान के चित्राल ले जाया गया था, जहां उन्हें पाकिस्तानी सैन्य शिविरों में प्रशिक्षण दिया गया। इन बयानों की भी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। यह घटनाक्रम पाकिस्तान द्वारा 21 सितंबर को अफगानिस्तान के भीतर किए गए हवाई हमलों के कुछ दिनों बाद सामने आया है। पाकिस्तान ने उन हमलों में 28 उग्रवादियों को मारने का दावा किया था। वहीं, अफगान अधिकारियों के अनुसार, हमलों में तीन नागरिकों की मौत हुई थी। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन (यूएनएमए) ने एक पुरुष, एक महिला और एक लड़की की मौत की पुष्टि की थी।

रूस के एमसी-21 विमानों की विदेशी डिलीवरी 2032 के बाद होगी : निर्माता

इरकुत्स्क। रूस के एमसी-21 यात्री विमानों की दूसरे देशों को डिलीवरी वर्ष 2032 के बाद शुरू होगी। विमान निर्माता कंपनी इरकुत्स्क एविएशन ने कहा है कि कंपनी की उत्पादन क्षमता के हिसाब से अब तक बुक ऑर्डर की पूर्ति की बाध्यता के कारण 2032 तक पहले निर्यात के लिए ऑर्डर 2032 के बाद की अवधि के लिए लिए जाएंगे।

इरकुत्स्क एविएशन प्लांट के सीईओ आंद्रे सोइनोव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कंपनी मित्र देशों को एमसी-21 विमानों की आपूर्ति की संभावनाओं पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कई देशों की ओर से विमान में रुचि दिखाई गई है और इसकी क्षमताओं को लेकर बातचीत, बैठकें तथा प्रस्तुतियां आयोजित की जा रही हैं। सोइनोव के मुताबिक, हाल ही में हुए एक अनुबंध के बाद कंपनी की उत्पादन क्षमता वर्ष 2032 तक पूरी तरह प्रतिबद्ध हो चुकी है। ऐसे में विदेशी बाजार के लिए कोई भी संभावित समझौता 2032 के बाद की अवधि के लिए होगा। उन्होंने कहा कि कंपनी के लिए उत्पादन क्षमता बढ़ाना तकनीकी रूप से संभव है, लेकिन फिलहाल ऐसा करने की कोई योजना नहीं है। उनके अनुसार, अतिरिक्त क्षमता तैयार करने और उसे बनाए रखने पर काफी खर्च आएगा तथा मांग में भविष्य में कमी आने की स्थिति में यह कंपनी के लिए चुनौती बन सकती है। सोइनोव ने बताया कि कंपनी उत्पादन को धीरे-धीरे अपने निर्धारित लक्ष्य तक बढ़ाने और स्थिर उत्पादन दर बनाए रखने की रणनीति पर काम कर रही है। फिलहाल कंपनी की योजना प्रति वर्ष 36 से अधिक एमसी-21 विमानों का उत्पादन नहीं करने की है। सितंबर में मॉस्को में रूसी नागरिक उड्डयन क्षेत्र के इतिहास के सबसे बड़े अनुबंधों में से एक पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके तहत एयरोफ्लोट को 90 एमसी-21 विमानों की आपूर्ति 2029 से 2032 के बीच की जानी है। इसके अलावा, पहले हुए एक अनुबंध के तहत एयरोफ्लोट को 2027 और 2028 में 18 एमसी-21 विमान दिए जाने हैं। एमसी-21 एक मध्यम दूरी का, नैरो-बॉडी यात्री विमान है, जिसे याकोवलेव कॉरपोरेशन ने विकसित किया है। विमान के विभिन्न संस्करणों में 163 से 211 यात्रियों के बैठने की क्षमता है। याकोवलेव, रोस्टेक की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन (यूएसी) का हिस्सा है।

ईरान अमेरिका से युद्ध के लिए 'पूरी तरह तैयार', लेकिन कूटनीति का रास्ता भी खुला : अराग्ची

तेहरान,एजेंसी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि उनका देश अमेरिका के साथ दोबारा युद्ध की स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन साथ ही वह कूटनीति के जरिए तनाव कम करने की कोशिश भी जारी रखे हुए है। ईरान सरकार की अंतरराष्ट्रीय समाचार नेटवर्क प्रेस टीवी के मुताबिक, अमेरिकी न्यूज एजेंसी को दिए एक इंटरव्यू में ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान किसी भी नए अमेरिकी हमले का मजबूती से सामना करने के लिए तैयार है, चाहे स्थिति कितने ही गंभीर संघर्ष में क्यों न बदल जाए। उन्होंने साथ ही कहा कि ईरान बातचीत और कूटनीति के लिए भी तैयार है और अब फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को करना है।

अब्बास अराग्ची की यह टिप्पणी उन खबरों के बीच आई है, जिनमें दावा किया गया है कि ट्रंप अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के बाद ईरान के खिलाफ फिर से सैन्य कार्रवाई पर विचार कर सकते हैं। हालांकि, अराग्ची ने कहा कि ईरान के लिए अमेरिकी चुनावों से अधिक उसके अपने राष्ट्रीय हित महत्वपूर्ण हैं। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने इस सप्ताह न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान बैठकों और मीडिया इंटरव्यू के जरिए होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के लिए कूटनीतिक प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप की ओर से आने वाले संदेश 'विरोधाभासी' रहे हैं। अराग्ची के अनुसार, ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से ईरान के प्रस्ताव को खारिज

करने की बात कही है, लेकिन मध्यस्थों के जरिए तेहरान को इस फैसले की कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है। अब्बास अराग्ची ने कहा कि युद्ध समाप्त करने वाले किसी समझौते के तहत ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के लिए तैयार है। इसके बदले तेहरान अपने फ्रीज किए गए फंड और संपत्तियों को जारी करने तथा अपने तेल की बिक्री की अनुमति चाहता है। ईरान की ये मांगें नई नहीं हैं और उनके अनुसार ये अमेरिका की पिछली प्रतिबद्धताओं का हिस्सा रही हैं। उन्होंने जून में दोनों देशों के बीच हुए समझौता ज्ञापन का भी उल्लेख किया, जिसमें अस्थायी युद्धविराम की योजना का जिक्र था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मध्यस्थता से हुआ यह समझौता कुछ ही दिनों में टूट गया और ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने समझौता ज्ञापन के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कीं। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में कूटनीति की ओर लौटने के लिए ईरान के पास बहुत कम कारण हैं, लेकिन इसके बावजूद वह बातचीत की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि 'शांति का कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि ईरान ने सैन्य, कूटनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों के साथ-साथ अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करने की अपनी क्षमता भी दुनिया के सामने प्रदर्शित की है। साथ ही, उन्होंने दोहराया कि सम्मान और न्याय पर आधारित बातचीत तथा ईरानी लोगों के अधिकारों और मांगों की गारंटी ही आगे बढ़ने का रास्ता है।

भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से नेपाल में कई जलविद्युत परियोजनाओं का उत्पादन बंद

काठमांडू,एजेंसी। नेपाल में लगातार हो रही बारिश, तेज हवाओं और बाढ़-भूस्खलन के कारण पश्चिमी हिस्से में ऊर्जा संरचनाओं को भारी नुकसान पहुंचा है। इसके चलते बिजली उत्पादन से लेकर प्रसारण और वितरण तक की व्यवस्था प्रभावित हुई है। गंडकी, लुंबिनी और कर्णाली प्रदेश के विभिन्न इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई है।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण के प्रवक्ता राजन ढकाल ने बताया कि, कालीगंडकी कॉरिडोर की 220 केवी प्रसारण लाइन के तहत म्याग्दी के दाना से पर्वत के कुश्मा तक के खंड में टावर नंबर 21 और 22 क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसी तरह कालीगंडकी कॉरिडोर के कुश्मा-नया बुटवल खंड की प्रसारण लाइन में भी फॉल्ट आया है। इसके कारण इस कॉरिडोर की प्रसारण लाइन से जुड़े करीब 200 मेगावाट बिजली उत्पादन प्रभावित हुआ है। बाढ़ के कारण कई प्रमुख जलविद्युत परियोजनाओं में बिजली उत्पादन बंद हो गया है। इनमें 140 मेगावाट की कालीगंडकी, 25 मेगावाट की अपर मादी, 44 मेगावाट की सुपर मादी, 20 मेगावाट की नामार्जुन मादी, 40 मेगावाट की सेती नदी, 25 मेगावाट की अपर दोर्दी, 50 मेगावाट की अपर मर्स्याङ्दी, 70 मेगावाट की मध्य मर्स्याङ्दी और 69 मेगावाट की मर्स्याङ्दी जलविद्युत परियोजनाएं शामिल हैं। मोदी समेत अन्य परियोजनाओं का उत्पादन भी प्रभावित हुआ है। इसके अलावा, राहुघाट जलविद्युत

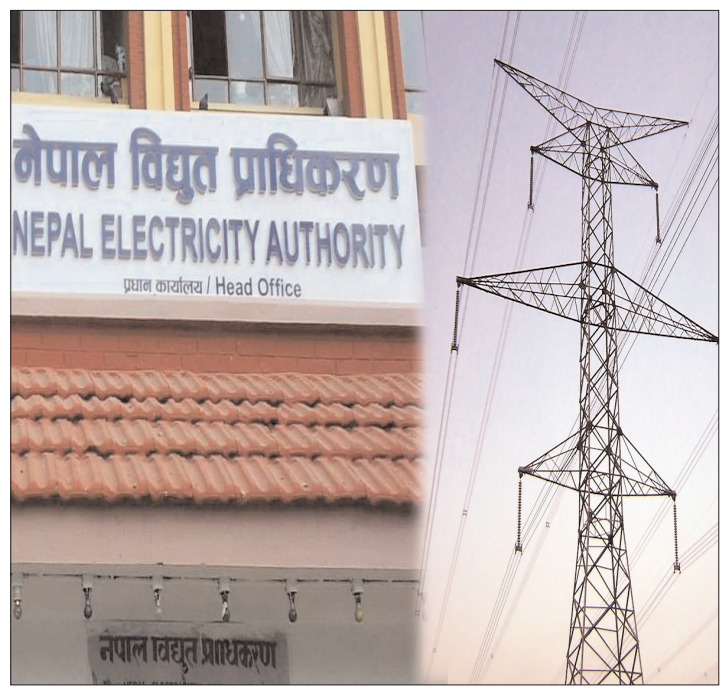

परियोजना के टेलरेस में भी क्षति पहुंची है।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण के अनुसार, प्रसारण और वितरण लाइनों को नुकसान पहुंचने के कारण बिजली उत्पादन भी प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि कई परियोजनाओं में संभावित नुकसान को रोकने के लिए एहतियात के तौर पर उत्पादन बंद किया गया है। स्थिति सामान्य होते ही परियोजनाओं को फिर से संचालन में लाया जाएगा। बाढ़ और भूस्खलन के कारण 220 केवी, 132 केवी, 33 केवी और 11 केवी की प्रसारण एवं वितरण संरचनाओं को भी नुकसान पहुंचा है। प्राधिकरण के अनुसार, नुकसान का प्रारंभिक विवरण जुटाने, बिजली आपूर्ति बाधित क्षेत्रों की पहचान करने, वैकल्पिक माध्यम से बिजली आपूर्ति शुरू करने और क्षतिग्रस्त संरचनाओं की तत्काल मरम्मत के लिए तकनीकी एवं मरम्मत टीमों को विभिन्न प्रभावित क्षेत्रों में भेजा गया है।

ईरान का दावा-आईआरजीसी ने होर्मुज जलडमरूमध्य में अमेरिका का दूसरा अंडरवॉटर ड्रोन पकड़ा

तेहरान,एजेंसी। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने दावा किया है कि उसकी नौसेना ने होर्मुज जलडमरूमध्य में जासूसी गतिविधियों में लगे अमेरिका के एक और ऑटोनॉमस अंडरवॉटर व्हीकल (एयूवी) को रोककर जब्त कर लिया है। यह सितंबर के बाद ऐसी दूसरी कार्रवाई बताई जा रही है। ईरान सरकार की अंतरराष्ट्रीय समाचार नेटवर्क प्रेस टीवी के मुताबिक, आईआरजीसी नौसेना ने रविवार को जारी बयान में कहा कि उसके बलों ने खुफिया जानकारी और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए एक 'समन्वित और जटिल ऑपरेशन' के तहत अमेरिकी अंडरवॉटर ड्रोन को पकड़ा। आईआरजीसी के अनुसार, यह ड्रोन होर्मुज जलडमरूमध्य में निगरानी और जासूसी गतिविधियों में शामिल था। ईरानी बलों ने जब्त किए गए ड्रोन की पहचान 'रेमस 600' के रूप में की है।

यह एक उन्नत ऑटोनॉमस अंडरवॉटर व्हीकल है, जिसे बिना चालक के समुद्र के भीतर विभिन्न मिशनों के लिए संचालित किया जा सकता है। आईआरजीसी ने कहा कि ड्रोन अब उसके विशेषज्ञों के कब्जे में है और उससे संबंधित जानकारी हासिल करने का काम किया जा रहा है। आईआरजीसी नौसेना ने अपने बयान में यह भी कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य बंद है और वह जलमार्ग में 'खतरनाक गतिविधियों और बिना अनुमति

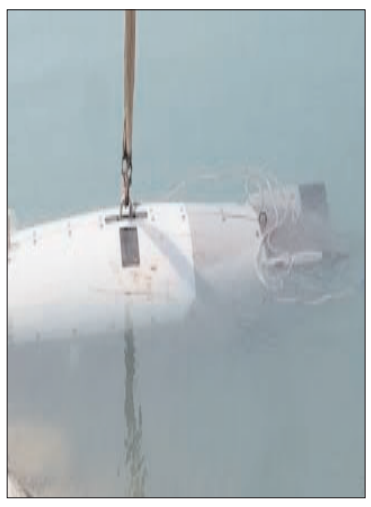

आवाजाही' के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगी। इससे पहले सितंबर में आईआरजीसी नौसेना ने दावा किया था कि उसने होर्मुज जलडमरूमध्य के प्रवेश द्वार के पास अमेरिका के एक अन्य उन्नत मानवरहित अंडरवॉटर व्हीकल को रोका और जब्त किया था। उस सिस्टम की पहचान 'डाइव-एलडी' (डाइव-एलडी) के रूप में की गई थी। आईआरजीसी के मुताबिक, डाइव-एलडी को अमेरिकी रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी एंडुरिल इंडस्ट्रीज ने विकसित किया है और इसे अमेरिकी नौसेना के मानवरहित अंडरसी व्हीकल कार्यक्रम के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

एक नजर

बुंदेलखंड के लिए बने आर्गेनिक बोर्ड और मिले विशेष पैकेज : राकेश टिकैत

महोबा,एजेंसी। बुंदेलखंड की वीरभूमि महोबा में सोमवार को किसान महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जमकर गरजे। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए एमपी और यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र को मिलाकर आर्गेनिक बोर्ड बनाने और बुंदेलखंड के लिए विशेष पैकेज की मांग की। सोमवार को जनपद मुख्यालय स्थित नवीन गल्ला मंडी में आयोजित किसान महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि बुंदेलखंड को जब तक सरकार हर साल राहत नहीं देगी, तब तक यहां काम चलने वाला नहीं है। टिकैत ने कहा कि बुंदेलखंड में किसानों और आमजनमानस के लिए शिक्षा और चिकित्सा फ्री मिलनी चाहिए, किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए, तभी यहां का पलायन रुकेगा। यहां की खनिज संपदा का 40 फीसदी हिस्सा यहीं पर खर्च किया जाए। आर्गेनिक से बुंदेलखंडी किसानों का बहुत भला होगा। इसके साथ ही यूपी-एमपी के बुंदेलखंड के हिस्से को मिलाकर ऑर्गेनिक बोर्ड बनाया जाए और बुंदेलखंड को विशेष पैकेज दिया जाए।

आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर टिकैत ने कहा कि बेईमानी करेंगे तो बीजेपी जीतेगी नहीं, तो कोई और भी जीतेगा। वोट चोरी तो हो रहा है और वोट चोरी हुआ है लेकिन विपक्ष भी तो कुछ काम करे अभी तक किसी को लाठी नहीं लगी है। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष कमजोर नहीं, डरा हुआ बताया और कहा कि डरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाह को जन्म देता है। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि अबकी बार नया काम होगा जो मजबूत हों, वही विधानसभा चुनाव लड़ें। प्रत्याशी पर्चे भरेंगे तो सरकार के लोग उन्हें डराएंगे, पर्चे वापस कराएंगे और उन्हें अपने पक्ष में करेंगे। विपक्ष वालों के हॉस्पिटल बंद कराएंगे और खनन बंद कराएंगे। इस तरह विपक्ष को डराया जाएगा। सीजेपी को लेकर कहा कि यही इनकी जड़ काटेगी। बुंदेलखंड में बनी मंडियों की बदहाली को लेकर टिकैत ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की प्लानिंग है कि मंडिया खंडहर हो जाएं, यहां माल न आए और ये बंद हो जाएं । व्यापारी बाहर चले जाएं। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अधिकारी सुधर जाएं, सरकार को खुश करने के लिए किसानों को परेशान न करें। सरकार के प्लान में अधिकारी शामिल न हों। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष राम खिलावन शुक्ला भारी संख्या में किसान मौजूद रहे हैं।

हर्ष संघवी ने एलावेलिन वलारिवन को 1.33 करोड़ रुपये के खेल प्रतिभा पुरस्कार से किया सम्मानित

गांधीनगर,एजेंसी। एशियन गेम्स 2026 में राइफल शूटिंग में दो सिल्वर मेडल जीतने वाली गुजरात की प्रतिभाशाली शूटर एलावेलिन वलारिवन को उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने खेल प्रतिभा पुरस्कार योजना के तहत 1.33 करोड़ रुपये का चेक प्रदान कर सम्मानित किया। जापान में आयोजित एशियन गेम्स 2026 में एलावेलिन ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल की व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए दो रजत पदक हासिल किए। उनकी इस उपलब्धि से गुजरात के साथ देश का नाम भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित हुआ है। एलावेलिन को बधाई देते हुए उपमुख्यमंत्री संघवी ने कहा कि गुजरात सरकार राज्य की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और उन्हें अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों की सफलता के पीछे उनकी मेहनत के साथ माता-पिता का योगदान भी महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने कहा कि डीएलएसएस योजना के तहत संचालित संस्कारधाम परिसर में शिक्षा प्राप्त कर चुकीं एलावेलिन वलारिवन ने एशियन गेम्स में गुजरात का गौरव बढ़ाया है। उनकी सफलता राज्य के हजारों युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है। खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गुजरात सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत एलावेलिन को अब तक कुल 2.41 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि दिए जाने की जानकारी दी गई। इसमें शक्तिदूत योजना और ओलंपिक प्रोत्साहन के तहत 1.33 करोड़ रुपये तथा डीएलएसएस योजना एवं खेल महाकुंभ जैसी योजनाओं के तहत 74 लाख रुपये की सहायता शामिल है। अहमदाबाद के मणिनगर क्षेत्र में रहने वाली 27 वर्षीय एलावेलिन वर्ष 2017-18 से गुजरात सरकार की शक्तिदूत योजना से जुड़ी हैं और वर्तमान में 'ए' कैटेगरी में शामिल हैं।

आत्मनिर्भर यूपी की राह में युवाओं के नवाचार को नई उड़ान, अलीगढ़ में यूपी राइज 2026

लखनऊ,एजेंसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के विजन को युवाओं के नवाचार, उद्यमिता और करियर अवसरों से जोड़ने की दिशा में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ में यूपी राइज 2026 का आयोजन किया गया। प्रदेश सरकार के इस प्रमुख कैंपस इनोवेशन और करियर अभियान का आयोजन टाइम्स नेटवर्क और ज़ूम के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने हिस्सा लेकर अपने नए विचारों और समाधान को मंच प्रदान किया।

अलीगढ़ चरण में पंजीकरण, सीएम-युवा योजना से जुड़े जागरूकता कार्यक्रम और सभागार सत्र समेत 2,300 से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की डिजिटल पहुंच 50 हजार से अधिक रही, जबकि ऑफलाइन पहुंच भी 5 हजार से अधिक दर्ज की गई। विश्वविद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम ने युवाओं के बीच नवाचार और उद्यमिता को लेकर उत्साह को सामने रखा। आरएमपीएसयू स्वयं रचनात्मक प्रतिभा, वैज्ञानिक सोच और विद्यार्थियों के करियर विकास को बढ़ावा देने पर जोर देता है। यूपी राइज 2026 के तहत परिसर में सीएम-युवा योजना जागरूकता स्टॉल, स्पिन द व्हील गतिविधि और ऑक्टोनॉर्म मेंटरशिप जोन लगाए गए। लॉबी और गलियारों में आयोजित इन गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को योजनाओं, करियर विकल्पों और

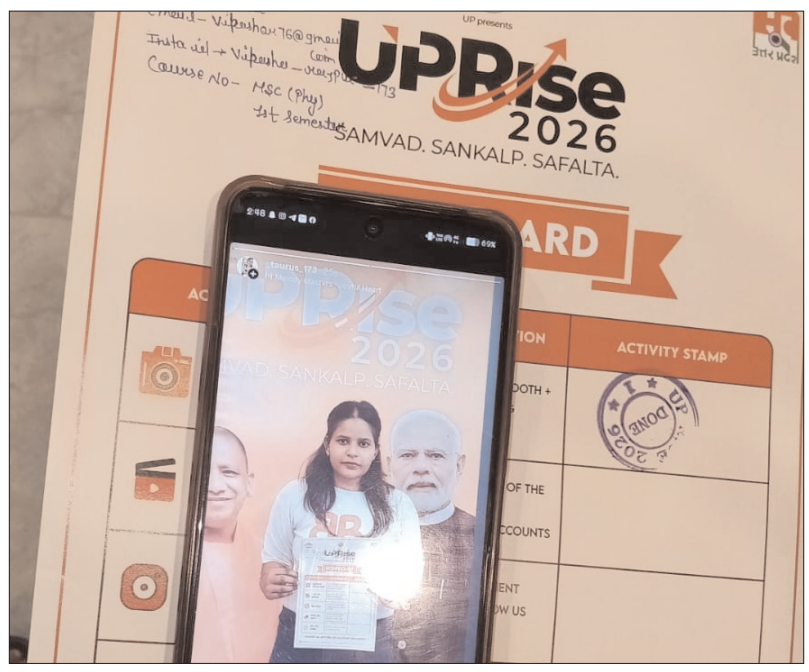

अपने विचारों को व्यावहारिक रूप देने के अवसरों से परिचित कराया गया। इसके बाद सभागार में बिल्ड फॉर यूपी पिच प्रतियोगिता का फाइनल आयोजित हुआ। प्रतियोगिता में चयनित 13 छात्र टीमों ने निर्णायकों और उपस्थित विद्यार्थियों के सामने अपने विचार प्रस्तुत किए। प्रतिभागियों ने स्थानीय समस्याओं के व्यावहारिक समाधान, नए व्यवसाय मॉडल और सामाजिक उपयोगिता से जुड़े प्रस्ताव रखे। प्रतियोगिता का विजेता प्रस्ताव तेज रोशनी वाली हेडलाइट्स के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से तैयार सुरक्षा-केंद्रित समाधान पर आधारित रहा।

सर्राफा बाजार में मामूली गिरावट, सोना और चांदी की चमक पड़ी फीकी

नई दिल्ली। घरेलू सर्राफा बाजार में सोमवार को शुरुआती कारोबार के दौरान सांकेतिक गिरावट का रुख बना हुआ नजर आ रहा है। भाव में आए बदलाव के कारण देश के ज्यादातर सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना आज 1,52,670 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,52,820 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना आज 1,39,940 रुपये प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,40,090 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। चांदी के भाव में भी मामूली कमजोरी आने के कारण ये चमकीली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में आज 2,44,900 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिक रही है।

दिल्ली में 24 कैरेट सोना आज 1,52,820 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,40,090 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,52,670 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,39,940 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 1,52,720 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,39,990 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना आज 1,52,720 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 1,39,990 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। इसी तरह कोलकाता में 24 कैरेट सोना 1,52,670 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,39,940 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। भोपाल में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,52,720 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,39,990 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। जयपुर में 24 कैरेट सोना 1,52,820 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,40,090 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,52,720 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,39,990 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। लखनऊ के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना आज 1,52,820 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर और 22 कैरेट सोना 1,40,090 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसके अलावा कर्नाटक, तेलंगाना और ओडिशा के सर्राफा बाजार में भी आज सोने के भाव में मामूली गिरावट आई है। इन तीनों राज्यों की राजधानियों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में 24 कैरेट सोना 1,52,670 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है।

कच्चे तेल की आंच में झुलसा घरेलू शेयर बाजार, निवेशकों को लगी 8.77 लाख करोड़ रुपये की चपत

नई दिल्ली,एजेंसी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में आई जोरदार तेजी, पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता विफल होने के बाद एक बार फिर बढ़ते तनाव और विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार बिकवाली की वजह से आज का दिन घरेलू शेयर बाजार के लिए ब्लैक मंडे बन गया। आज के कारोबार में सेंसेक्स 1,179 अंक तक फिसल गया। इसी तरह निफ्टी भी 378 अंक तक लुढ़क गया। आज की गिरावट के कारण सेंसेक्स 73 हजार अंक के स्तर से भी नीचे आ गया। इसी तरह निफ्टी भी 23 हजार अंक के स्तर से लुढ़कते हुए 22,800 अंक से भी नीचे पहुंच गया। बाजार में मची बिकवाली की आंधी की वजह से बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज पौने नौ लाख रुपये से भी ज्यादा घट गया।

आज के कारोबार की शुरुआत भी कमजोरी के साथ हुई थी। बाजार खुलने के थोड़ी देर बाद ही चौतरफा बिकवाली शुरू हो गई, जिसकी वजह से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सूचकांक गिरते चले गए। हालांकि, दिन के दूसरे सत्र की शुरुआत में खरीदारों ने कुछ देर लिवाली का जोर बनाने की कोशिश भी की, लेकिन बिकवाली का दबाव इतना अधिक था कि उनकी कोई भी कोशिश सफल नहीं हो सकी। पूरे दिन के कारोबार के बाद सेंसेक्स 1.52 प्रतिशत और निफ्टी 1.56 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुए। बीएसई का सेंसेक्स आज 160.91 अंक यानी 0.22 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 73,734.83 अंक के स्तर पर खुला। बाजार खुलने के कुछ देर बाद ही बिकवाली शुरू हो गई, जिसकी वजह से इस सूचकांक की स्थिति कमजोर होती चली गई। शेयरों की लगातार हो रही बिक्री के कारण शाम तीन बजे के थोड़ी देर पहले यह सूचकांक 1,179.51 अंक यानी 1.60 प्रतिशत टूट कर 72,716.23 अंक के स्तर तक गिर गया। हालांकि, आखिरी आधे घंटे के कारोबार में हुई मामूली खरीदारी के कारण सेंसेक्स दिन के निचले स्तर से सांकेतिक रिकवरी कर 1,124.02 अंक यानी 1.52 प्रतिशत की गिरावट के साथ 72,771.72 अंक के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स की तरह ही एनएसई के निफ्टी ने आज 75.60 अंक यानी 0.33 प्रतिशत फिसल कर 23,064.90 अंक के स्तर से कारोबार की शुरुआत की। बाजार खुलते ही खरीदारी का सपोर्ट मिलने पर यह सूचकांक ओपनिंग लेवल से करीब 15 अंक की रिकवरी कर 23,080.25 अंक के स्तर तक पहुंचा। इसके तुरंत बाद बाजार में जोरदार बिकवाली शुरू हो गई। लगातार हो रही बिकवाली के कारण शाम तीन बजे के करीब यह सूचकांक 378.30 अंक यानी 1.63 प्रतिशत लुढ़क कर 22,762.20 अंक के स्तर तक गिर गया। अंत में इंट्रा-डे सेटलमेंट की वजह से हुई खरीदारी के कारण निफ्टी दिन के निचले स्तर से करीब 18 अंक सुधर कर 360.25 अंक यानी 1.56 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 22,780.25 अंक के स्तर पर बंद हुआ।

बड़ी डिग्री नहीं, बड़ा उद्देश्य जीवन को बनाता है बड़ा : राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार

रांची,एजेंसी। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने विद्यार्थियों का आह्वान किया कि वे अपने ज्ञान और प्रतिभा का उपयोग केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित न रखें, बल्कि बड़े उद्देश्य के लिए करें। उन्होंने कहा कि बड़ी डिग्री से बड़ा जीवन नहीं बनता, बल्कि बड़ा उद्देश्य जीवन को बड़ा बनाता है। राज्यपाल सोमवार को झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (जेयूटी), रांची के द्वितीय दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि विद्यार्थी ऐसे समय में विश्वविद्यालय से निकल रहे हैं, जब विज्ञान और तकनीक मानव जीवन एवं कार्यक्षेत्र को तेजी से बदल रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष विज्ञान जैसे क्षेत्रों में नई संभावनाएं उभर रही हैं। वहीं, डेटा गोपनीयता, साइबर सुरक्षा और डीपफेक जैसी चुनौतियां भी सामने हैं। ऐसे में भविष्य केवल तकनीकी दक्षता रखने वालों का नहीं, बल्कि तकनीक का उपयोग विवेक, नैतिकता और मानवीय मूल्यों के साथ करने वालों का होगा।

राज्यपाल ने कहा कि तकनीकी शिक्षा विद्यार्थियों को समस्याओं को समझने और उनके व्यावहारिक समाधान खोजने की क्षमता देती है। इसलिए लक्ष्य केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं, बल्कि अपने ज्ञान और कौशल के माध्यम से नए अवसर और रोजगार का सृजन करना भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर नवाचार एक सवाल से शुरू होता है कि किसी चीज को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। निरंतर सीखना, प्रश्न पूछना और नई संभावनाओं की तलाश करना ही प्रगति का आधार है। विद्यार्थियों को समस्या के कारण के साथ-साथ उसके समाधान पर भी विचार करना

चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि झारखंड प्राकृतिक संसाधनों के साथ युवा प्रतिभा और व्यापक संभावनाओं से समृद्ध राज्य है। जेयूटी को अपने तकनीकी ज्ञान और अनुसंधान को राज्य की वास्तविक जरूरतों से जोड़ना चाहिए। जल, ऊर्जा, खनन, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यावरण, ग्रामीण विकास और जनजातीय क्षेत्रों में तकनीक आधारित स्थानीय समाधान विकसित किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब प्रयोगशाला का ज्ञान धरातल की जरूरतों से जुड़ता है, तभी तकनीक की वास्तविक शक्ति सामने आती है। राज्यपाल ने विद्यार्थियों से तकनीकी दक्षता के साथ सामाजिक जिम्मेदारी को भी समझने की अपील की। उन्होंने कहा कि तकनीकी ज्ञान तभी सार्थक है, जब उसका उपयोग समाज और राज्य की समस्याओं के समाधान में किया जाए। झारखंड की स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने से शिक्षा और तकनीक का लाभ व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। द्वितीय दीक्षांत समारोह में तकनीकी और प्रबंधन पाठ्यक्रमों के टॉपर विद्यार्थियों को शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। कुल आठ विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल मिला। इनमें चार बीटेक और चार एमटेक व एमबीए स्तर के विद्यार्थी शामिल हैं। बीआईटी सिंदरी के विद्यार्थियों के हिस्से 8 में से 5 स्वर्ण पदक आए हैं। इनमें प्रीति कुमारी, आलोक रंजन, आरती कुमारी, शालिनी भारद्वाज और अविनाश कुमार शामिल हैं। वहीं, जेयूटी मुख्य परिसर, नामकुम (रांची) के विद्यार्थियों ने एमटेक एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में 2 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं, इनमें राहुल कुमार और चंद्रकांत कुमार शामिल हैं, जबकि, बोकारो स्थित जीजीएसईएसटीसी कैंपस की छात्रा शहनाज फरहीन ने एमबीए में गोल्ड मेडल हासिल किया है।

जामिया ने UI ग्रीनमेट्रिक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026 में वैश्विक स्तर पर 334वां स्थान हासिल किया

सद्भावना टुडे, संवाददाता

नई दिल्ली। जामिया मिल्लिया इस्लामिया (JMI) ने वैश्विक सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए UI ग्रीनमेट्रिक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026 में दुनिया भर में 334वां स्थान प्राप्त किया है। वर्ष 2025 में जामिया 376वें स्थान पर था। इस तरह विश्वविद्यालय ने अपनी वैश्विक रैंकिंग में 42 स्थान का सुधार दर्ज किया है।

रैंकिंग में जामिया ने भारत में 13वां और एशिया में 192वां स्थान हासिल किया है। यह उपलब्धि सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरणीय जिम्मेदारी और सतत कैंपस विकास के प्रति विश्वविद्यालय की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। UI ग्रीनमेट्रिक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स, यूनिवर्सिटास इंडोनेशिया से जुड़ी एक अंतरराष्ट्रीय सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग पहल है। इसमें विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन सतत विकास और कैंपस सस्टेनेबिलिटी से जुड़े विभिन्न मानकों के आधार पर किया जाता है। वर्ष 2026 के संस्करण में दुनिया भर के विश्वविद्यालयों के प्रदर्शन का सस्टेनेबिलिटी से संबंधित प्रमुख संकेतकों के आधार पर आकलन किया गया। इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कुलपति प्रो. मजहर आसिफ ने फैकल्टी सदस्यों, छात्रों, शोधकर्ताओं, पूर्व छात्रों और कर्मचारियों सहित पूरे जामिया

परिवार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह पहचान शैक्षणिक उत्कृष्टता, पर्यावरणीय जिम्मेदारी, सतत विकास और उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के प्रति विश्वविद्यालय के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। कुलपति ने विश्वास व्यक्त किया कि जामिया आने वाले वर्षों में अपनी सस्टेनेबिलिटी पहलों को और मजबूत करेगा तथा इस क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल करेगा। जामिया के रजिस्ट्रार प्रो. मो. महताब आलम रिज़वी ने भी इस उपलब्धि को विश्वविद्यालय के लिए गर्व का विषय बताया। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर JMI की शैक्षणिक एवं संस्थागत स्थिति को मजबूत करने में विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों और इकाइयों के सामूहिक प्रयासों की सराहना की।

विश्वविद्यालय ने इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल (IQAC) के योगदान को भी महत्वपूर्ण बताया। IQAC की निदेशक प्रो. रफ़त परवीन और उनकी टीम के नेतृत्व में गुणवत्ता आश्वासन, संस्थागत डेटा प्रबंधन, रैंकिंग एवं एक्रेडिटेशन प्रक्रियाओं, सस्टेनेबिलिटी से संबंधित डेटा संग्रह तथा साक्ष्य-आधारित प्रशासन पर लगातार काम किया गया है। जामिया के अनुसार, यह उपलब्धि विश्वविद्यालय की विभिन्न फैकल्टी, विभागों, केंद्रों, प्रशासनिक इकाइयों, शिक्षकों, छात्रों, शोधकर्ताओं और कर्मचारियों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। सस्टेनेबल कैंपस प्रैक्टिस, पर्यावरण प्रबंधन, संसाधनों का संरक्षण, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और जिम्मेदार संस्थागत विकास में किए जा रहे प्रयासों ने विश्वविद्यालय की वैश्विक सस्टेनेबिलिटी स्थिति को मजबूत किया है। UI ग्रीनमेट्रिक रैंकिंग में जामिया की लगातार प्रगति विश्वविद्यालय द्वारा सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरणीय जागरूकता और जिम्मेदार संसाधन प्रबंधन को अपने शैक्षणिक, शोध और प्रशासनिक तंत्र में शामिल करने के प्रयासों को रेखांकित करती है। वैश्विक स्तर पर 334वें, भारत में 13वें और एशिया में 192वें स्थान के साथ जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने सस्टेनेबिलिटी और संस्थागत उत्कृष्टता के क्षेत्र में अपनी निरंतर प्रगति दर्ज की है।

देश का औद्योगिक उत्पादन अगस्त में 8 फीसदी बढ़ा, विनिर्माण-बिजली का रहा बेहतर प्रदर्शन

नई दिल्ली,एजेंसी। देश का औद्योगिक उत्पादन अगस्त में 8 फीसदी बढ़ा, जबकि जुलाई में इसमें 7.4 फीसदी की वृद्धि हुई थी। यह नई श्रृंखला के तहत जारी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) का 5वां मासिक आंकड़ा है। अगस्त, 2025 में देश के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 4.7 फीसदी की वृद्धि हुई थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सोमवार को जारी आंकड़ों में बताया कि विनिर्माण क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन और बिजली एवं गैस आपूर्ति में मजबूत वृद्धि से औद्योगिक उत्पादन को गति मिली है। आईआईपी की इस बढ़ोत्तरी में मध्यवर्ती वस्तुओं, पूंजीगत वस्तुओं और टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं का सबसे अधिक योगदान रहा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के मुताबिक अगस्त महीने में आईआईपी में सालाना आधार पर आठ फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है। इस दौरान विनिर्माण क्षेत्र नौ फीसदी और बिजली एवं गैस आपूर्ति क्षेत्र 12.3 फीसदी बढ़ा है। एनएसओ आंकड़ों के अनुसार खनन एवं संबद्ध क्षेत्र में अगस्त के दौरान 5.6 फीसदी की गिरावट आई, जबकि पिछले साल इसी महीने में इस क्षेत्र का उत्पादन

15.8 फीसदी बढ़ा था।

एनएसओ ने इस साल जुलाई में जारी आईआईपी के पहले आंकड़े को 6.7 फीसदी के अस्थायी अनुमान से संशोधित कर अब 7.4 फीसदी कर दिया गया है। चालू वित्त वर्ष 2026-27 में अप्रैल-अगस्त के दौरान आईआईपी वृद्धि दर 6.7 फीसदी रही है, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 4.2 फीसदी रही थी।आंकड़ों के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र के 23 में से 18 उद्योग समूहों में अगस्त महीने में सालाना आधार पर वृद्धि दर्ज की गई। इस दौरान वाहन, ट्रेलर एवं सेमी-ट्रेलर के विनिर्माण में 25.2 फीसदी, विद्युत उपकरण विनिर्माण में 30.9 फीसदी और अन्य परिवहन उपकरण विनिर्माण में 25.3 फीसदी की वृद्धि दर्ज हुई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के मुताबिक उपयोग आधारित वर्गीकरण के अनुसार अगस्त में प्राथमिक वस्तुओं का सूचकांक 111.8, पूंजीगत वस्तुओं का 140.7, मध्यवर्ती वस्तुओं का 131.8 और बुनियादी ढांचा एवं निर्माण वस्तुओं का 132.5 रहा। टिकाऊ उपभोक्ता और गैर-टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के सूचकांक क्रमशः 129.4 और 114.3 रहे। इसके अलावा अगस्त में उपयोग आधारित वर्गीकरण के तहत प्राथमिक वस्तुओं में 3.5 फीसदी, पूंजीगत वस्तुओं में 16.9 फीसदी, मध्यवर्ती वस्तुओं में 13.7 फीसदी, बुनियादी ढांचा एवं निर्माण वस्तुओं में 6.4 फीसदी, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं में 11.1 फीसदी और गैर-टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं में 2.1 फीसदी की वृद्धि दर्ज हुई है।

मुद्रक, प्रकाशक, स्वामी, सैफुल्लाह सिद्दिकी द्वारा आरडी प्रिंटिंग एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-24, सेक्टर-08, नोएडा (यूपी), से छपवा कर एन-81, बटला हाउस, जामिया नगर पुलिस स्टेशन, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 से प्रकाशित किया। सर्वाधिकार सुरक्षित, किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा। (संपादक- सैफुल्लाह सिद्दिकी)